असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

02 जुलाई, 2019

षोडश विधान सभा | मंगलवार,तिथि 02 जुलाई, 2019 (ई0)
त्रयोदश सत्र | 11 आषाढ़, 1941(श0)

(कार्यवाही प्रारंभ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी ।

(व्यवधान)

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : बैठिये । सदन चलने दीजिए । बैठिये । आप जिस फैसले में शामिल थे उसको क्यों बाधित कर रहे हैं ? वह सब मत लाइए । बैठिये ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि -

''दिनांक 01 जुलाई, 2019 के कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर सभा की सहमति हो ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

''दिनांक 01 जुलाई, 2019 के कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर सभा की सहमति हो ।

समिति ने निम्न सिफारिशें की हैं -

1. शुक्रवार, दिनांक 28 जून, 2019 को निर्धारित वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरणी का उपस्थापन शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई, 2019 को गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के पूर्व हो । शेष कार्य यथावत् रहेंगे ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रतिवेदन पर सभा की सहमति हुई ।

प्रश्नोत्तर काल

श्री ललित कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय, हमलोग कार्य-स्थगन के माध्यम से कल सरकार से जवाब...

अध्यक्ष : तब आज क्यों कार्य स्थगित कर रहे हैं ?

श्री ललित कुमार यादवः महोदय....

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे । मो0 आफाक आलम ।

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न संख्या-39 माननीय सदस्य श्री (मो0) आफाक आलम ।

माननीय सदस्य श्री (मो0) आफाक आलम ।

अनुपस्थित ।

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न संख्याः 40 श्री संजय सरावगी

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गए।)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, 1. उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या-514 दिनांक 03.4.2013 के द्वारा नए प्राथमिक विद्यालयों के लिए न्यूनतम 20 डिसमील भूमि दान देने वाले दानदाता अथवा उनके द्वारा इच्छित व्यक्ति के नाम पर प्राथमिक विद्यालय का नाम रखे जाने का प्रावधान है ।

(व्यवधान)

2. उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि दरभंगा जिला मुख्यालय के वार्ड नं0-9 स्थित रत्नोपट्टी ठठेरी टोला के विश्वनाथ ठठेरी द्वारा 01कट्ठा अर्थात् 4.363 डिसमील जमीन वहाँ संचालित प्राथमिक कन्या विद्यालय के लिए दान में दिया गया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ललित जी, अगर आपकी की इच्छा है कि सदन की कार्यवाही नहीं चले, माननीय सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जाएं तो बता दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्रीः 3. भूमिदाता द्वारा दान में दी गई भूमि निर्धारित मापदंड से कम है । अतः भूमिदाता के नाम पर संबंधित विद्यालय के नामकरण किए जाने की अर्हता पूरा नहीं करता है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ललित जी, कल आप ही लोग इतना गंभीर विषय उठा रहे थे, मैंने अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए और इस विषय के लोक महत्व को देखते हुए हमने इसको स्वीकृत किया, कार्य-स्थगन प्रस्ताव को । सदन की अनुमति

से उस पर विमर्श भी हुआ दो घंटे का । अब आप किसी मंत्री के इस्तीफे के लिए... अगर बाकी सारे सदन और सदस्यों का काम नहीं होने देना चाहते हैं तो.....

(व्यवधान)

अब चलने दीजिए और आप सदस्यों का काम नहीं होने देना चाहते हैं तो हम एक मिनट में 2.00बजे तक के लिए... ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: महोदय, जिन सवालों को कल विपक्ष के माननीय सदस्यों ने कार्य-स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से लाया गया और आसन के तरफ से उसको स्वीकार किया गया और सभी कार्यों को रोककर उस पर बहस कराई गई है और उसका जवाब भी सरकार के तरफ से माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी ने दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया और उसके बाद इस तरह से सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं । तारांकित प्रश्न है । तारांकित के बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है और इतने महत्वपूर्ण सवाल हैं और उसके बाद भी उसका जवाब लेना नहीं चाहते हैं महोदय, इस प्रकार से सदन चाहता है और सरकार चाहती है कि जो माननीय सदस्य हैं और जिन प्रश्नों को माननीय सदस्यों ने उठाया है उसका जवाब सरकार देना चाहती है और बिहार की जनता के सवालों का हल करना चाहती है और विपक्ष में यह जो हमारे माननीय सदस्य बैठे हैं वो नहीं चाहते हैं कि बिहार के ज्वलंत सवालों का हल हो, माननीय सदस्यों के सवालों का हल हो और सदन की कार्यवाही को बाधित करना चाहते हैं । महोदय, यह सदन चलता है नियमावली से, सदन चलता है कानून से, सदन चलती है परिपार्टी से । हठधर्मिता से सदन नहीं चलता है और आपको भी विचार करना चाहिए । आपको भी सोचना चाहिए कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत मेहनत और परिश्रम करके माननीय सदस्य सवाल करते हैं और सवालों को उठाते हैं उसको हल करने दीजिए और जब शून्यकाल आए तो इन सवालों को उठाइए, जब कार्य-स्थगन का समय हो तो कार्य-स्थगन पर चर्चा कीजिए । नियम के हिसाब से चलिए तो मैं समझता हूं कि राज्य का, राज्य की जनता का भी हित होगा और आपके प्रति भी बिहार की जनता अच्छा भावना से सोचेगी लेकिन आप इस तरह से हठधर्मिता का परिचय दीजिएगा तो बिहार की जनता ने लोकसभा में जिस तरह से रिजेक्ट किया है आपको, आने वाले दिनों में भी आप उसी तरह से रिजेक्ट हो जाइएगा । इसलिए बिहार की जनता के सवालों का हल होने दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री संजय सरावगी : महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि जमीन जितनी होनी चाहिए उससे कम मात्रा में दी गई लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया कि

जितनी होनी चाहिए, नीतिगत् उससे कम मात्रा में दी गई है लेकिन यह विद्यालय ब्रजकिशोर कन्या विद्यालय के नाम से इसका नामकरण कर दिया गया जबकि ब्रजकिशोर के नाम से न कोई भूमिदाता है, न कोई वहां परिवार है । हो सकता है 1996 में कोई रहा होगा लेकिन जो भूमिदाता है उसके नाम से नहीं है तो इसीलिए मैंने आग्रह किया था कि क्या सरकार ब्रजकिशोर कन्या के स्थान पर विश्वनाथ ठठेरी जी जो यह जमीन दिए, तब वहां विद्यालय संचालित है, गरीब बच्चियां वहां पढ़ रही है तो क्या सरकार स्व0 विश्वनाथ ठठेरी जी के नाम पर इस विद्यालय का नामकरण करना चाहती है ? यह मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से ।

(व्यवधान)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, मूल प्रश्न में उसकी चर्चा नहीं है । उन्होंने जिनके नाम पर नामकरण की बात कही है, विश्वनाथ ठठेरी, तो उन्होंने जो जमीन दान में दिया, वह पर्याप्त नहीं है, वह निर्धारित मापदंड है, उससे कम है वह जमीन, इसलिए जब तक कि उतनी जमीन नहीं दान दी जाती है तब तक यह करना संभव नहीं है ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं तब ब्रजकिशोर जी के नाम से कैसे उसका नामकरण हो गया ? जो जमीन नहीं दिया, जो वहां कोई है नहीं, सामाजिक व्यक्ति भी नहीं है वहां, इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, और जो जमीन दिया उसके नाम पर नहीं हुआ । मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि विश्वनाथ ठठेरी जी ने जमीन दिया, गरीब की कन्या वहां पढ़ रही है तो उनके नाम पर नहीं हो सकता है तो दूसरे के नाम पर जो भूमिदाता नहीं है, वहां कोई रहता नहीं है तो उसके नाम पर तो आपने कर दिया और जो जमीन दिया उसके बारे में कह रहे हैं कि 20 डिसमल जमीन होना चाहिए । शहर के बीचो-बीच का जगह है सर । वह परिवार जमीन दिया है विद्यालय का तो जरूर उस परिवार को वहां प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, उसके नाम से होनी चाहिए । मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी एक बार जांच करा लेंगे जिसके नाम से यह विद्यालय है उसकी जांच कराकर क्या उसपर कार्रवाई करेंगे, मैं यह जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से ।

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार, मंत्रीः महोदय, मैं माननीय विपक्ष के सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपनी जगह पर जाएं, आसन ग्रहण करें और सदन की कार्यवाही में हिस्सा लें और माननीय सदस्य जिन सवालों के लिए चिंतित हैं महोदय, उसके समाधान का रास्ता माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल अपने वक्तव्य के दौरान किया है.....क्रमशः

टर्न–02/कृष्ण/02.07.2019

(व्यवधान जारी)

श्री श्रवण कुमार,मंत्री (क्रमशः) और अगर कोई सुझाव है माननीय सदस्यों के पास तो लिखित रूप से सरकार को भिजवा दें, उस पर भी सरकार अमल करेगी । सरकार तो हर तरह से चाहती है कि जो सवाल हैं, उनके हल हों । लेकिन इनको चिंता नहीं है महोदय । इनके पास संवेदना नहीं है । ये बच्चों की लाश पर राजनीति करना चाहते हैं । महोदय, अगर इनके पास संवेदना होती तो नेता,विपक्ष कहां हैं? क्या नेता,विपक्ष मुजफ्फरपुर गये ? विधान सभा के विपक्ष के नेता भी मुजफ्फरपुर नहीं गये और उस सदन के नेत्री माननीय श्रीमती राबड़ी देवी भी नहीं गयी वहां के बच्चों और उनके परिवार के लोगों का आंसू पोछने के लिये। महोदय, ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं । इस तरह से समस्या का हल नहीं होता है । समस्या का हल तो बातचीत से होता है, सुझाव से होता है और इन्होंने कल जो सुझाव दिये हैं, उनको सरकार ने गंभीरता से लिया है । जब उन सवालों पर एक बार चर्चा हो गयी, कार्य स्थगन प्रस्ताव पर सदन में चर्चा हो गयी, हर दिन अगर प्रश्नों को बाधित करेंगे, हर दिन सदन का समय बर्बाद करेंगे तो मैं समझता हूं कि इनके पास संवेदना नहीं है । ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और पॉलिटिकल माईलेज लेना चाहते हैं । महोदय, हठधर्मिता से सदन नहीं चलता है, नियम और नियमावली से सदन चलता है । इसलिए मैं एक बार पुनः आग्रह करते हैं कि माननीय सदस्यगण अपनी–अपनी जगह पर जाय और सदन की कार्यवाही को चलने दें ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब दिला दिया जाय । श्री विश्वनाथ ठठेरी ने जमीन दिया और विद्यालय ब्रज किशोर के नाम से कैसे हो गया ? इसका जवाब जरा करवा दीजिये अध्यक्ष महोदय । जिन्होंने जमीन दिया उसको सम्मान मिलना चाहिए । उस पूरे इलाके में उस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है । महोदय, जरा, उसका जवाब करा दीजिये माननीय मंत्री जी से ।

(व्यवधान जारी)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के मूल प्रश्न में इसकी चर्चा नहीं है कि किस व्यक्ति के नाम से वह पूर्व से चल रहा है । महोदय, यह बहुत ही पुराना विद्यालय है । माननीय सदस्य अगर चाहते हैं तो मैं इसकी जांच करा दूंगा और जांच के बाद जो बातें आयेगी, उसके अनुसार कार्रवाई की जायेगी ।

श्री संजय सरावगी : जांच करा दीजिये ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण ।

और जोर से बोलिये । कौन बोल रहे हैं ? और जोर से चिल्लाईये । इसीलिये आपको जनता चुनकर भेजी है ? चिल्लाईये, चिल्लाईये ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्य सुरेन्द्र जी, आप हमको चुने हैं, मालूम है । हम कहां इंकार करते हैं ।

(व्यवधान जारी)

बिल्कुल । माननीय सदस्य सुरेन्द्र जी, इसीलिये कल आपकी बात मानकर हम कार्य-स्थगन-प्रस्ताव को स्वीकृत किये थे । आप हमको चुने हैं इसीलिये ।

(व्यवधान जारी)

एक मिनट सुन लीजिये न । अंत में आपकी जो इच्छा है, वह तो पूरी कर देंगे। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिये ।

कर दें ?

(व्यवधान जारी)

अब सदन की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित की जाती है ।

टर्न-3/अंजनी/दि0 02.07.2019

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । वित्तीय-कार्य ।

वित्तीय-कार्य

माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श का आज दूसरा दिन है । अब माननीय सदस्य श्री प्रभुनाथ प्रसाद ।

श्री प्रभुनाथ प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, आज मुझे बजट के पक्ष में बोलने का मौका मिला, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को और अध्यक्ष महोदय आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ । महोदय, बिहार एक विकासशील राज्य की तरफ बढ़ रहा है और बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए हम सब लोग मिलकर जनता के प्रतिनिधित्व के रूप में यहां पर आये हैं ताकि अपने-अपने क्षेत्र में विकास का कार्य कर सकें और बिहार का विकास हो सके । उसी के तहत हमलोग अपने-अपने क्षेत्र में बिहार के हर कोने की विकास की बात आपके माध्यम से हमलोग करते हैं । विकास को लेकर वर्ष 2004-05 में देखें तो उस समय जो बजट पेश हुआ था, उसमें करीब 24 हजार करोड़ रूपये का बजट पेश हुआ था और तब से लेकर आज तक हमलोग इसपर गौर करें तो आज यह बजट करीब नौ गुणा बढ़ चुका है । महोदय, बिहार में सबसे पहले लॉ एण्ड ऑर्डर की जो व्यवस्था थी, आज बहुत बढ़िया ढंग से चल रही है । वर्ष 2005 के पहले यहां पर बहुत सी घटनायें हो रही थी और जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के गद्दी को संभाला तब से आज बिहार विकासशील राज्य की तरफ दौड़ रहा है और विकास दर भी बढ़ रहा है । महोदय, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने गद्दी संभाला तो उन्होंने शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया । आज के बजट में भी सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा पर दिया गया है ताकि हमारे बिहार के जो भी हमारे छात्र, नौजवान हैं, वे शिक्षा ग्रहण कर सकें । जैसे कि हमलोग केरल का उदाहरण लेते हैं। तो केरल में शिक्षा दर सबसे ज्यादा है और उसी के तर्ज पर हमारा बिहार भी केरल से आगे जाय और देश में एक शिक्षित राज्य बन सके, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है । शिक्षा से ही विकास संभव है ।

महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2019-20 का जो बजट पेश किया, वह करीब 2 लाख 501 करोड़ रूपये का है, जो वर्ष 2004-05 का नौ गुणा है । जब तक हमलोग अपने क्षेत्र की समस्याओं को, बिहार की समस्याओं

को नहीं समझेंगे, उसको नहीं बता पायेंगे तबतक बजट बड़ा नहीं हो पायेगा । महोदय, इससे साबित होता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी बिहार के विकास के लिए सोचते रहते हैं और जो उनको ध्यान में आता है, उसको बजट में प्रावधान करते हैं । शिक्षा के बाद सबसे अहम् समस्या रहता है, वह स्वास्थ्य की है। अभी हाल ही में स्वास्थ्य के क्षेत्र में माननीय मंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने बजट में पी0एम0सी0एच0 को एक विश्वस्तरीय अस्पताल बनाने के लिए वहां पर करीब पांच हजार बेड बनाये जायेंगे, उसके लिए 5540 करोड़ रूपया का प्रावधान किया गया है ।

अध्यक्ष : प्रभुनाथ जी, आपको 2-3 मिनट में समाप्त करना होगा, इसलिए जल्दी-जल्दी प्राथमिकता के हिसाब से बोलें ।

श्री प्रभुनाथ प्रसाद : महोदय, इसके साथ-साथ करीब 11 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणायें की गयी, जिसमें छपरा, पूर्णियां, समस्तीपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सिवान, बक्सर, भोजपुर एवं जमुई जिला हैं । महोदय, उसी तरह मेडिकल के क्षेत्र में, गृह विभाग के क्षेत्र में और महिलाओं के शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा ध्यान दिया गया है । महोदय, जब तक इस देश में महिलायें शिक्षक नहीं होंगी तबतक पुरूषों के बराबर नहीं आयेगी और बिहार राज्य हमारा विकसित नहीं हो पायेगा । इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छा प्रावधान किया है । हर घर में बिजली, महोदय, सरकार का टारगेट था कि दिसम्बर 2018 तक हर घर में बिजली पहुंचाया जायेगा लेकिन राज्य के 39 हजार गांवों में समय से पूर्व बिजली पहुंचा दिया गया है और आज बिजली करीब 24 घंटा में 22 घंटा देहातों में रहती है । तो यह सब विकास का एक उदाहरण है। महोदय, सिंचाई के क्षेत्र में भी सरकार किसानों के लिए जो नये जलाशय हैं या जो इन्द्रपुरी का बराज है, उसको एक जलाशय बनाने की सरकार ने घोषणा की, जिससे किसानों का पटवन सुविधाजनक हो सकेगा और पानी का स्टोर हो सकेगा । महोदय, बरसात के मौसम में वहां पर बराज रहने के कारण किसानों को समय पर पानी नहीं मिल पाता है और अगर जलाशय बनेगा तो जो नहर क्षेत्र के लोग हैं, उन किसानों को समय पर सोन नदी द्वारा पानी का सप्लाई किया जा सकता है । खासकर, जब हमलोग दूसरे राज्यों में जाते हैं, वहां के बड़े-बड़े शहरों में तो देखते हैं कि वहां पर मेट्रो की व्यवस्था की गयी है और मेट्रो ट्रेन चलती है । यहां पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने मेट्रो के लिए बजट में प्रावधान किया है ताकि पटना में भी मेट्रो ट्रेन चल सके । तो यह हमारी विकसित राज्य की पहचान है । महोदय, इसके साथ-साथ बिहार के विकास के लिए जो

सड़क है कि हर टोला को सड़क से जोड़ने का जो सरकार का प्रावधान है, उसके तहत हर टोला को सड़क से जोड़ा गया है और जो सड़कें बची हुई हैं, उसको भी उचित समय में जोड़ दिया जायेगा । विकास के साथ सात निश्चय और शराबबंदी, कन्या बाल विवाह पर जो रोक लगाने की सरकार का प्रावधान है, उसपर हमारी सरकार सतत् चिंतित रहती है । महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहूंगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में.....

अध्यक्ष : इस सुझाव के बाद आप अपना भाषण समाप्त कर दीजिए ।

श्री प्रभुनाथ प्रसाद : स्वास्थ्य के क्षेत्र में माननीय लोग भी जाते हैं हॉस्पीटल में, अस्पताल में तो उन अस्पतालों में जो मरीजों का ऑपरेशन होता है, तो उस ऑपरेशन थियेटर के बाहर एक ऐसा सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाया जाय ताकि उनके परिजन जान सकें कि हमारे परिवारजनों के साथ क्या हो रहा है । कुछ ऐसे होते हैं कि वेंटिलेशन पर मरे हुए लोगों को रखा जाता है और परिवार के लोग यही जानते हैं कि आई0सी0यू0 में हमारा परिवार है और उसको बताया नहीं जाता है । यह एक बहुत बड़ी बात है । यह राज्य के हित में बात है तो इसपर मैं चाहूंगा कि इसपर कार्रवाई हो और सरकार इसपर संज्ञान ले । इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद महोदय ।

टर्न-4/राजेश/2.7.19

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी जी आपके दल ने आपको 20 मिनट का समय आवंटित किया है ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: बढ़ा भी सकती है सर । महोदय, माननीय वित्त मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी ने हालॉकि 12 फरवरी, 2019 को ही अपना 104 पेज का बजट सदन के समक्ष उपस्थापित किया था, मगर उसपर कोई बहस नहीं हो सकी थी, इसलिए कि एलेक्शन की वजह से हम सारे लोग भाग दौड़ की स्थिति में थे और सेशन को कट डाउन करना पड़ा और हम सब लोग एलेक्शन में चले गये तो बजट की प्रॉयरिटी सेकेंड्री हो गयी और जो चुनाव है वह हम सभी लोगों के लिए प्राईमरी हो गया, मगर सरकार लाती है प्रपोजल तो हमको मानना ही पड़ता है । अब रही बात महोदय कि जो बजट है, यह सरकार की नीतियों का, सरकार की प्राथमिकता का और कितनी बड़ी चादर इनकी है, उस हिसाब से कितना पैर फैलाना है, उसका एक तरह से लेखा-जोखा बजट में होता है, आय-व्यय का ब्योरा भी बजट में होता है । अब सरकार जो पेश करती है बजट तो वह कहती है कि हमारा बजट क्रांतिकारी बजट है, इससे गुणात्मक परिवर्तन हो जायेगा, गरीब लोग

जो हैं अब वह गरीबी रेखा से उपर उठ करके अमीरी रेखा में आ जायेंगे, जो रिक्शा पर चलने वाले लोग हैं अब वे मारुति और चार चक्के में चलने लगेंगे यानि की सत्तापक्ष उसमें हम हो या आप, यह सच्चाई है कि जो बजट पेश करता है वह कहता है कि हमारा बजट क्रांतिकारी बजट है लेकिन हमलोग इसको क्रांतिकारी बजट नहीं कहते हैं बल्कि इसको कहते हैं ट्रेडिशनल रुटिन बजट, इसलिए कि जब सरकार चलाना है तो जो राशि है, उस राशि का विभिन्न विभागों में प्रावधान करना, उनकी स्कीमों के तहत उनका लेखा-जोखा जो है, वह वित्त विभाग रखती है, वित्त विभाग किसी पर खुश रहा तो कुछ ज्यादा दे दिया और किसी ने कम खर्चा किया तो उसको खर्चा कम कर दिया । अब महोदय, हम इसको सरसरी निगाह से देख रहा था कि बजट में सब लोग इसका जिक्र जरुर करते हैं कि जो हमारा बजट है यह कितने का कुल टोटल बजट है, इसमें प्रतिबद्ध व्यय कितना होने वाला है और कितना है हमारी योजना का आकार वगैरह है मगर कोई यह जिक्र नहीं करता इस पुस्तक में कि हमने जो बजट लाया और बजट के बाद भी संवैधाानिक प्रावधान के हिसाब से चूंकि यह बजट अनुमानित है, अनुमान के आधार पर है तो कभी सरकार को जब जरुरत पड़ती है तो फस्ट सप्लिमेंट्री में पैसा प्रावधान कर लिया, सेकेंड सप्लीमेंट्री में पैसा प्रावधान कर लिया, थर्ड सप्लीमेंट्री में कर लिया तो इसतरह से हमारे वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया, उसमें कहा कि साहब एक लाख 76 हजार 990 करोड़ रुपये से अधिक, यानि 2018-19 में था एक लाख 76 हजार 990 और 2019-20 में नौ गुणा बढ़कर अब हो गया दो लाख 501 करोड़, अब इसमें सरकार से मांगियेगा तो सरकार देगी, लेकिन वह तो अपने प्रतिवेदन में देती नहीं है कि भईया आपने पैसा लिया इतना, खर्चा कितना किया और सरेंडर कितना करते हैं तो ये कहते हैं कि हम तो अनुमान के आधार पर इतना पैसा ले लिये, मगर जब बजट पेश होता है, तब हम अपना पीठ थपथपाते हैं अपना कि मेरा बजट का आकार बढ़ गया और जब पैसा हम सरेंडर करते हैं तो जय-जय-सीताराम, चुपचाप रह जाते हैं तो अब तो हम पूरा तो नहीं, चूंकि आपने समय निर्धारित किया है, मैं सिर्फ तीन साल का जो इन्होंने राशि सरेंडर किया है, उसका लेखा-जोखा सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ । महोदय, 2016-17 में जो बजट एस्टीमेटेड था वह एक लाख 44 हजार 696.27 था और फिर रिभाईज्ड स्टीमेट जो है वह एक लाख 54 हजार 327.47, अब आप इस किताब में खोजते रह जाइये कि साहब आपने कितना पैसा सरेंडर किया, तब हमलोगों को बताना पड़ता है कि कितना सरेंडर किया आपने तो इन्होंने उस साल सरेंडर कितना किया 28 हजार 25 करोड़ रुपया से अधिक इन्होंने सरेंडर किया, अब उसके बाद आ

जाइये 2017-18 में बजट स्टीमेट था एक लाख 60 हजार 85.69 और फिर फस्ट, सेकेंड और थर्ड लेकर एक लाख 72 हजार 884 हुआ और सरेंडर कितना किया तो 36 हजार 457.26, उसी तरह से 2018-19 में, हम तो मात्र तीन ही साल का फीगर दे रहे हैं..... (व्यवधान)

अध्यक्ष: सिद्दिकी साहब ! आप कितना अच्छा बोल रहे है, आप इधर देखकर बोलते जाइये। कहॉ आप इधर-उधर, दॉये-बॉये देखते रहते हैं ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: महोदय, ये लोग आर0एस0एस0 के ट्रेंड लोग हैं, इनलोगों को सिखाया गया है कहॉ पर क्या सब चुटकी लेना है । महोदय, 2018-19 में इनका बजट स्टीमेट था एक लाख 76 हजार 990.27 और रिभाईज्ड स्टीमेट हो गया एक लाख 90 हजार 918.72 और इन्होंने खर्चा किया एक लाख 56 हजार 545.27 यानि की सरेंडर किया 34 हजार 373.45, अब मैं बहुत सी बातों पर जाना नहीं चाहता हूँ । मैं अब इन्हीं से पूछना चाहता हूँ, इनके बजट का प्रावधान भी देखा, स्वास्थ्य का । हमने स्वास्थ्य के कार्यक्रमों को भी देखा है, जो राशि प्रावधानिक की गयी है, उसको भी देखा है, मगर जो बच्चे मर गये मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से, अब आप बताइये महोदय कि जब इतनी बड़ी संख्या में राशि सरेंडर की जा रही है तब आप 100 बेड का आई0सी0यू0 नहीं बना सकते थे, आप कोई अनुसंधान केन्द्र नहीं खोल सकते थे, वगैरह-वगैरह, मगर हम तो कहेंगे कि आपकी प्राथमिकता अलग है, आपकी प्राथमिकता रंग-रोगन की, आपकी प्राथमिकता है डेंटिंग-पेंटिंग की, आपकी प्राथमिकता है साज-सज्जा की, अभी हम सिर्फ इतना कह दे महोदय कि यह जो अभी एम0एल0ए0 फ्लैट बन रहा है महोदय, मैंने एक दिन बड़े गौर से उसको घूमकर देखा, मुझको बड़ा ही ताज्जुब हुआ कि इस सरकार ने अपनी प्रॉयरिटी में एम0एल0ए0 फ्लैट का नया निर्माण कराना किस बुद्धि से सोचा यह तो बुद्धि की बलिहारी है, मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि वह पुराना एम0एल0ए0 फ्लैट अभी 50 नहीं बल्कि 75 साल तो कम से कम चलता ही महोदय, उसमें जो लकड़ियॉ थी, बारमटिक थी, वह लकड़ियॉ कहॉ गयी, उसका हिसाब-किताब चाहिए, उसका हिसाब-किताब लेंगे.....

मोदी जी आप इतने उतावले क्यों होते रहते हैं और आप उकसाते हैं हमको कहने के लिए । महोदय, इनकी प्रॉयरिटी एम0एल0ए0 फ्लैट का निर्माण कराना, कन्स्ट्रक्शन कराना, पटना का बिहार म्यूजियम बनाना, बुद्धा पार्क बनाना, वगैरह वगैरह जो है, अब जो लोग रहे हैं कन्स्ट्रक्शन साईड में या जो लोग ठीकेदारी से अवगत हैं, वे तो जानते हैं कि कन्स्ट्रक्शन में बहुत सारा चीज उसमें फिक्स रहता है अरे भईया ! यही कन्स्ट्रक्शन एम0एल0ए0 फ्लैट का अभी बनाने की

आवश्यकता नहीं थी, मगर चेहरा चमकाने के लिए नाम दर्ज कराने के लिए और लूट कराने के लिए आपने इतने अच्छे एम0एल0ए0 फ्लैट को तोड़कर जैसा फ्लैट बना रहे हैं, उसमें तो परिवार वाला कोई नहीं रहेगा ।

क्रमशः

टर्न-5/सत्येन्द्र/ 02-07-2019

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी(क्रमशः): जो उसका निर्धारित अवधि था, अब अगर बोलेंगे तो कहियेगा कि बोलते हैं, बोलेंगे तो कहियेगा कि बोलता है ।

अध्यक्षः आप क्या चाहते हैं कि आप बोलियेगा तो लोग कहें कि आप नहीं बोलते हैं ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकीः अब इसकी जांच हो जाय कि इसका ठीकेदार कौन है, उसकी निर्धारित अवधि क्या थी, वह ब्लैकलिस्ट होने लायक है या नहीं है वगैरह वगैरह । मैं कह रहा था यह महोदय, चूंकि मोदी जी ने छेड़ दिया, अब रही बात अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि जो फंक्शन आपका होता है उसमें बहुत राजनीति हमलोग नहीं करते हैं मगर हमारे आदरणीय मोदी जी इतना इनका फितरक है कि किसी न किसी पर, जैसे बहुत अच्छी बहाली हुई ईमानदारी से(व्यवधान) महोदय, मोदी जी बहुत सीजन पोलटिशियन है, हमको तो लगता है अमित शाह को रिप्लेश यही कर सकते हैं और एक ही चीज जो है, मतलब आप टाईट क्यों हो गये, अरे भाई आप बुद्धिमान आदमी है और इतने दिनों से राजनीति में है लेकिन अब आपको किसी को गाली देने से थोड़े ही पद मिलने वाला है क्या? अब आप ऐसे जगह पर आ गये हैं कि आपकी जब भी सरकार रहेगी तो पद मिलेगा ही और हम तो यह देख रहे हैं कि कब आप अमित शाह जी को रिप्लेश करते हैं और उस जगह पर पहुंचते हैं । हमारी ये शुभकामना है मगर महोदय जो नियुक्ति पत्र बंट रहा था, उस वक्त भी इन्होंने कहा कि आपके दो-दो बी0पी0एस0सी0 के चेयरमैन और फलां लोग जेल में गये । ठीक बात है गये, गलती करेंगे तो जायेंगे लेकिन आप अपने टाईम का क्यों भूल गये, अवर सेवा चयन पर्षद के अध्यक्ष और कौन कौन लोग आज जेल में हैं, वे हमारे समय के नहीं है, अवर सेवा चयन पर्षद के अध्यक्ष आपके समय के बनाये हुए हैं, आपकी सरकार के बनाये हुए हैं और सरकार कोई भी हो, चाहे आपकी सरकार हो या मेरी सरकार हो, किसी के बारे में आरोप लगाते हैं तो समदृष्टि होनी चाहिए । आप अवर सेवा चयन पर्षद का भी जिक्र कर देते तो हम थोड़े ही ये बात करते महोदय। महोदय, आज के अखबार में, आज ही का यह अखबार है, तीन अखबार है महोदय, एक तो दैनिक भास्कर है और एक है दैनिक जागरण और एक है हिन्दुस्तान । मोदी जी आपको दिखलाना

चाहते हैं दो तस्वीर जो है महोदय बड़ा व्यूटीफूल है, ये है गांधी मैदान का और इसमें जो पानी लगा हुआ है तो हमको लगता है कि उसको झील में परिवर्त्ति कर देने से फोटो बड़ा ही अच्छा लगेगा, एक तो यह फोटो और दूसरा हमलोग जो विधान-सभा जाते हैं, आप कैबिनेट में जाते होंगे, एक उसके मेन गेट का है फोटो और एक आज जो जी0एस0टी0 के बारे में व्यवसायी लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रया दी है, उसमें जो अध्यक्ष है बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स के पी0के0अग्रवाल साहब उनकी भी प्रतिक्रिया है । आपने देखा ही होगा इसलिए हम नहीं इसको दोहराना चाहते हैं । मैंने इस वजह से इन दोनों फोटो को दिखलाया कि नगर निगम का कोई पदाधिकारी, मतलब कि 15-20 रोज पहले अपना बयान दिया अखबार में कि अब एक बूंद पानी पटना में लग नहीं सकता है । अरूण जी, याद रखियेगा एक बूंद पानी लग नहीं सकता है, मोदी जी को तो पानी में हेल कर जाना पड़ता है। महोदय, अब जो इनकी प्रायोरिटी है, उस प्रायोरिटी में हमारा शिक्षा होना चाहिए था, हमारा स्वास्थ्य होना चाहिए, हमारा पानी का जमाव होना चाहिए था, गरीबों के कार्यक्रम होने चाहिए थे बगैरह बगैरह लेकिन उसका अभाव है इसमें महोदय, अब हम कहें, ये बो कुछ नहीं है ये बजट, वह बजट..

अध्यक्ष: ये सब बोलने से काई फायदा नहीं है, समय भी आपका अब दो ही तीन मिनट बचा है ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: हां, पांच मिनट महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि देखिये इनका जो प्रायोरिटी है, वह प्रायोरिटी क्या है, हमने दो बार ऐज ए वित्त मंत्री बजट पेश किया था। यहां स्वाभाविक है कि उसमें अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का जो है वह बजट बढ़ा था। वह बजट बढ़ा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का, आपको माफ नहीं किया जायेगा । आप भी मंत्रिपरिषद के मेम्बर हैं, जो पहले 873.19 करोड़ रू0 का उसका बजट था और उस समय इधर जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, क्या क्या नहीं कहा, मुसलमान का बढ़ा दिया, फलां का बढ़ा दिया, ये कर दिया, वह कर दिया मगर आपके आने से इतना फायदा हुआ, नीतीश जी पर असर पड़ा कि वह 873.19 करोड़ से घटकर अब हो गया 2019-20 में 424 करोड़ रू0 । आप नारा दे रहे हैं सब का साथ सब का विश्वास, सब का विकास बगैरह बगैरह। अब उसी तरह महोदय, हालांकि हमारी जो प्रायोरिटी होती है, मैं दावे के साथ और ठोक कर कह सकता हूँ कि जब हमारे पास आया वित्त का बजट एप्रुवल के लिए तो ये जो गर्दनीबाग है महोदय, इसमें क्या क्या बनने का है उसका पूरा प्रस्ताव था हमने कहा कि इसमें फोर्थग्रेड इम्पलाई के क्वार्टर का है या नहीं है? कहा कि फोर्थ ग्रेड इम्पाई का नहीं है तो हमने कहा कि मैं पटना

हाईस्कूल में पढ़ता था, उस समय गर्दनीबाग में दो महला एक रूम का हुआ करता था फोर्थ ग्रेड इम्पलाई का क्वार्टर, जिसमें वे लोग पूरे परिवार के साथ उसमें रहते थे और वह ध्वस्त हो गया है इसलिए जबतक आप फोर्थ ग्रेड इम्पलाई का गर्दनीवाग में प्रावधान नहीं करेंगे और वह भी क्वार्टर उस तरह का दो रूम का क्वार्टर, दो रूम, एक ड्राइंग का रूम, एक नहाने का बाथरूम, एक टॉयलेट, किचन, मुझे खुशी है कि उसको इन्होंने कांट छांट नहीं किया है और वह बनने जा रहा है। इसी तरह महोदय, 2016-17 में हमने बता दिया, जैसे एक इन्होंने घोषणा भी किया, कमजोर तबके के लिए हमारी प्रतिबद्धता, कमजोर तबके लिए प्रतिबद्धता ही रहती तो बच्चे ही मरते, कमजोर तबके के लिए प्रतिबद्धता में इन्होंने अपना एक कार्यक्रम घोषित किया उसके तहत एस0सी0/एस0टी0 उद्यमी के लिए एक योजना बनायी है, पांच लाख रू0 अनुदान और पांच लाख रू0 बैंक लोन से दिलाकर के जो एस0सी0/एस0टी0 के जो उद्यमी है, उनको रोजगार खड़ा करने के लिए ऋण दिलाया जायेगा । अभी तक कुल 38 हजार लोगों ने इस योजना के तहत आवेदन पत्र दिये हैं जिसमें मात्र 1700 का अभी चयन हुआ है, वाह रे एस0सी0/एस0टी0 का प्रेम, अब एस0सी0/एस0टी0 का प्रेम तब जगेगा जब चुनाव आयेगा, हिन्दू, मुसलमान, पाकिस्तान, उस टाईम में जो है एस0सी0/एस0टी0 अछूत नहीं है, मगर जब देने की बात हो तो उस वक्त जो है यह अछूत हो जाता है।(क्रमशः)

टर्न-6/मधुप/02.07.2019

....क्रमशः....

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : मेरे पास महोदय.....

अध्यक्ष : अब अंतिम बात कह दीजिये ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : जब आप कह रहे हैं महोदय, तो मैं आपका आदर करता हूँ....

अध्यक्ष : मैं भी आपका ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, ऐसा है कि हमारे टाईम में 2016-17 के बजट में प्रावधान किया गया था कि राजगीर में एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, स्पोर्ट्स एकेडमी बनेगी । राजगीर का सवाल था तो यह तो हो रहा है और उसी में यह भी प्रावधान किया गया था कि हर प्रमंडलीय शहरों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद सुविधाओं, आधारभूत संरचना को विकसित किया जायेगा तो उस दिशा में.. (व्यवधान) अरे भाई, बोधगया में भी होना न चाहिए था, भागलपुर में भी होना चाहिए था, मुजफ्फरपुर में भी होना चाहिए था, छपरा में भी होना चाहिए था ।

श्रवण जी तो बड़े खुश हैं कि इनके इलाका का हो गया । महोदय, मैं लास्ट में.....

(व्यवधान)

दरभंगा के बारे में पहले कह चुके हैं । दरभंगा में आपके तरह विधायक नहीं होने के बावजूद हमने अपने विधायक राशि से पैसा लगाकर दो-दो चौक - कर्पूरी चौक, लोहिया चौक को कैसा किया है, आप तो जानते हैं । फिर जो इनडोर स्टेडियम के लिए अपने राशि से बहेड़ा में रह कर दिया है....

अध्यक्ष : आप उनके एजेंडा पर बोलने लगे ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : अब लास्ट है, महोदय । अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे, बार-बार कहते हैं - हमलोगों का जंगलराज था, यह तो रामराज है । रामराज में तो क्राइम समाप्त ! अब तो कोई आदमी अपना दरवाजा बंद ही नहीं करता है, खोलकर सोता है ! यह सरकार का ऑकड़ा है, हमारा आंकड़ा नहीं है । कॉगनिजेबल क्राइम - 2005 से हम शुरू करते हैं-1,04,778, 2006 में हो गया-1,10,716, 2007 में 1,18,176, 2008 में 1,30,693, 2010 में 1,37,572, 2011 में 1,47,633, 2013 में 1,84,961 और 2018 में 2,62,802 । तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है । आपको जो शिक्षा मिली है, उस शिक्षा में यह बताया गया है, आपने जो डिग्री प्राप्त की है, उसमें आपको यह बताया गया है कि 2,62,802 यह कम होता है 1,04,778 से । यही आपको पढ़ाया गया है तो आप बोलिये, अपने पढ़ाई के हिसाब से बोलिये । उसी तरह से महोदय, मर्डर का, डकैती का, रॉबरी का, बल्गरी का, थेफ्ट का, रॉइट का, किडनैपिंग का, किडनैपिंग फोर रैनसम, सबका है, इस राज्य में अपराध बढ़े हैं । कितना मैनेज कीजियेगा मीडिया ? कितना 24 घंटा दिखाते रहियेगा टी0वी0 ? मगर अब तो वही टी0वी0 आप पर लग गया है न मुजफ्फरपुर वाले में ? इसीलिये जो सच है, वह सच है, जो झूठ है तो झूठ है । आप सरकार में हैं, आपको जनता के काम करने की जिम्मेदारी है । आप कीजिये मगर खाली पीठ मत थपथपाइये । हमारा राज जंगलराज, इनका राज रामराज ? रामराज अगर यही है तो ऐसा रामराज नहीं चाहिए। अभी तो आप हैंग-ओवर में हैं मगर हैंग-ओवर देश की जनता और बिहार की जनता ही उतारेगी चाहे मेरा हो या आपका हो । मगर यह हैंग-ओवर ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, इस बजट में न प्राथमिकता गरीबों के लिए तय है...

(व्यवधान)

महोदय, मैं एक बात कह कर समाप्त करूँगा । सरकार ने कहा था चीनी मिल को बेच दिया । हैं कोई दरभंगा-मधुबनी वाले इधर ? महोदय, माननीय मुख्यमंत्री 2007 में गये थे रैयाम । कहा कि यह रैयाम चीनी मिल का जो चिमनी

है, इससे जबतक धुआँ नहीं निकलेगा तबतक हम वोट माँगने नहीं आयेंगे । क्या हाल है रैयाम चीनी मिल का ? सकरी का, लोहट का, हसनपुर का ? हसनपुर का तो थोड़ा चल भी रहा है, और दूसरे जगह का ? अगर यह एग्रो-बेस्ड स्टेट है, अगर यहाँ गरीबी-रेखा से नीचे रहने वाले ज्यादा लोग हैं, देहात में 89 परसेंट लोग रहने वाले हैं तो जबतक आपका बजट और बजट का आकार गाँव के लिए, गरीब के लिए, गरीब-गुरबा के लिए नहीं होगा तबतक आप अपनी पीठ थपथपाते रहिये, एम0एल0ए0 फ्लैट बनाते रहिये, रंग-रोगन लगाते रहिये, डेंटिंग-पेंटिंग, पाउडर वगैरह लगाकर चेहरा चमकाते रहिये । यह ज्यादा दिन नहीं चलता है, बहुत लोग आये और बहुत लोग गये । इसीलिये अब आप जाने वाले हैं । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : श्री अमित कुमार टुन्ना । 10 मिनट समय है आपका ।

श्री अमित कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज मुझे यहाँ पर 2019-20 के आय-व्ययक पर बोलने का मौका मिला है । बोलने को तो बहुत कुछ है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस राज्य में लोग डरे हों, गरीब लोग डरे हों, जिस राज्य में पढ़े-लिखे लोग डरे हों, जिस राज्य में व्यवसायी वर्ग के लोग डरे हुये हों, उस राज्य में क्या व्यय और क्या आय ? सोचने की बात है कि आज कोई भी व्यक्ति दिन-दहाड़े कहीं जा रहा है, दिन-दहाड़े किसी टाउन में किसी दुकान में डकैती हो जा रही है या कहीं अगर कोई गाँव जा रहा है, बस से उतार कर दिन-दहाड़े मार दिया जा रहा है लेकिन सरकार सोयी हुई है । सरकार की नींद नहीं टूट रही है, प्रशासन अंकुश नहीं लगा पा रहा है । इस तरह से भय से भरा जो बिहार बना हुआ है, कहीं भी राज्य के किसी भी कोने में देख लीजिये, कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन पेपर को देखने को नहीं मिलता है कि आज फलाँ जगह किसी को गोली मार दिया गया तो किसी बच्ची का बलात्कार हो गया है । कैसे चलेगा बिहार, यह सोचने की बात है और मंथन करना पड़ेगा माननीय मुख्यमंत्री जी को । पहले की बात थी, लगता है जैसे मोदी जी कुछ बोलते थे और उसको लोग सोचता था कि बोल दिये, होगा-होगा नहीं होगा, वही हाल आज हमारे बिहार का हो गया है । माननीय मुख्यमंत्री जब शुरू के वर्ष में आये थे तो बहुत काम किये तो हमलोगों को लगा था कि कुछ होगा, कुछ बदलाव होगा लेकिन आज फिर से हमलोग उसी स्थिति में आ गये हैं । चाहे किसी भी मुद्दे पर चले जाइये, आज बिहार के स्कूलों की स्थिति देख लीजिये कि बिहार में बच्चे बैठे रहते हैं, शिक्षक पढ़ाने को नहीं हैं । बड़े-बड़े बिल्डिंग बन गये हैं लेकिन वहाँ कोई शिक्षक देखने को नहीं मिलता है । यह समझने का विषय है । आज कहीं भी चले जाइये, हमारे सीतामढ़ी में, दो साल हो गया बाढ़ आये हुये, दयनीय स्थिति है, कोई भी ग्रामीण

सड़क नहीं है जहाँ होकर लोग आ-जा सके । आज तक दुरूस्त नहीं हुआ दो साल में तो क्या होगा ?

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह ने माननीय सभापति का आसन ग्रहण किया ।)

वृद्धा-पेंशन का वही हाल है । गाँव-गाँव में लोग ब्लॉक ऑफिस का चक्कर लगा-लगाकर थक गये हैं लेकिन उनको आज तक वृद्धा-पेंशन नहीं मिल रहा है । (व्यवधान) चलिये मेरे यहाँ, आप तो मेरे बगल के विधान सभा क्षेत्र से आती हैं, आप चलिये, अगर बन गया होगा तो मान जायेंगे । बड़े शर्म की बात है, आप विधान सभा में गलत बोल रही हैं, सबों के बारे में कि लोग क्या बोलता है, आप अपना सोचिये । (व्यवधान) हम जान रहे हैं, आहत हैं बेचारी, सदमा में हैं । चलिये ठीक है, हो सकता है कि स्पेशल आपके लिए बना होगा ।

महोदय, स्वास्थ्य विभाग को ले लीजिये । किसी भी हॉस्पीटल में एक जगह भी बता दीजिये, कहीं भी मरीज का ऑपरेशन होता हो, यह बता दीजिये । अभी-अभी हमारे यहाँ एक माता और बच्चे का देहांत हो गया क्योंकि डॉक्टर की कमी थी, डॉक्टर समय पर नहीं आ पाये । हर जगह एजेंट बहाल है, उस एजेंट का पैसा कहाँ जाता है, यह सोचने का विषय है । अगर हॉस्पीटल में कोई पेसेंट जाता है तो उसको एजेंट पहले ही बरगलाता है कि यहाँ मत जाइये, वहाँ जाइये, करते-करते शाम तक उसको प्राइवेट हॉस्पीटल में लेकर चला जाता है । तो इसमें भी लगता है कि जैसे आजकल कमीशन हर घर नल-जल योजना में उपर से नीचे कमीशन जा रहा है, आज हॉस्पीटल में दलालों के माध्यम से भी सरकार को कहीं न कहीं से कमीशन देने का काम, कलेक्शन करने का काम हो रहा है । यही कारण है कि आज हमारे अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है । इसपर सरकार को विचार करना पड़ेगा कि क्या कारण है कि हमारे बिहार में डॉक्टर आ नहीं रहे हैं, तीन-चार साल हमलोगों को इस विधान सभा में आये हुये हो गया, जब पहले सत्र में आये थे तभी हमलोगों को आश्वासन दिया गया था माननीय मंत्री जी की तरफ से कि बहाली होगी, शिक्षक की बहाली होगी, डॉक्टर की बहाली होगी । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कब होगा, कैसे होगा ?

....क्रमशः....

..... क्रमशः .....

श्री अमित कुमार : आपको इसपर मंथन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि आज डॉक्टर हमारे यहां क्यों नहीं आना चाह रहे हैं, क्यों नहीं ब्लॉक में जाना चाह रहे हैं, ध्यान देने की चीज है, क्योंकि जो डॉक्टर लोग पढ़ते हैं, उनको भी सही मूल्य मिलना चाहिए, उनको भी सही तनख्वाह मिलना चाहिए ताकि ब्लॉक में रहकर भी वह अपने बाल-बच्चे का भरण-पोषण अच्छे से कर पाये, अपने बच्चे को वे अच्छे से पढ़ा पाये, तभी कोई अच्छे डॉक्टर जाकर आपको मिलेंगे । आपको 40-50 हजार रू0 में अच्छे डॉक्टर नहीं मिलेंगे । आपको इसपर गहन मंथन करना पड़ेगा कि बिहार के लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाय, कैसे उनको हर परदे पर आगे लाने की जरूरत है । लेकिन यह सरकार इस बारे में नहीं सोच रही है, बहुत दयनीय स्थिति है । हमलोग जब आज गांव में जा रहे हैं, भूख से लोग तड़प रहे हैं । लोग कहते हैं कि पोषाहार मिल रहा है, कुपोषण के शिकार बच्चे नहीं हैं लेकिन हमको तो लग रहा है कि आंगनबाड़ी का पूरा सिस्टम बिहार में अभी फेल है । यह जो चमकी बुखार है, इसका एक्जामपुल सेटअप करता है कि आंगनबाड़ी का आपका सिस्टम अगर ठीक होता तो इतने ज्यादे बच्चे जो चमकी बुखार से मरे, उनका इस तरह से देहान्त नहीं होता क्योंकि आंगनबाड़ी में बच्चों का रजिस्ट्रेशन होता है, उनके लिए पोषाहार देने की व्यवस्था है लेकिन यह प्रुफ करता है कि पूरे बिहार में आंगनबाड़ी कहीं सही तरीके से नहीं चल रहा है । उन्होंने आंकड़ा नहीं दिया, इसका रिजल्ट हुआ कि मुजफ्फरपुर में सैंकड़ों बच्चों का देहान्त हुआ । इसका कमीशन भी आज बन्दरवाट हो रहा है । आपको इसपर गहन चिन्तन मंथन करना पड़ेगा कि इस सिस्टम का फेल्योर ही मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार का मेन रिजन है । अगर यह सिस्टम चालू रहता तो हर गांवों में , हर वार्ड में एक-एक जगह आंगनबाड़ी का है तो आंगनबाड़ी लोग अपने से इसको कंट्रोल कर सकती थी, ध्यान दिया जा सकता था, लेकिन यह सरकार सोयी हुई है, इस सरकार को अपना पेट भरने से, अपना पैसा भरने से, अपने लोगों का काम करने से फुर्सत नहीं है तो वह क्या देखेगी कि बच्चा कहां मर रहा है और बच्चा क्या कर रहा है ? आप किसी भी डिपार्टमेंट की बात कर लीजिए, हमारे यहां गन्ना मिल है, पिछले साल का भुगतान नहीं हो पाया है, तीन करोड़ रू0 बाकी है, अभी 125 करोड़ रू0 का गन्ना देकर के हमारे किसान बैठे हुए हैं और टुक-टुक नजर लगाये रहते हैं कि 15 प्रतिशत, 15 प्रतिशत करके कब हमलोगों का भुगतान होगा, जरा इसपर सोचने की जरूरत है । हमलोगों को भी तनख्वाह का हरेक एक तारीख को इन्तजार रहता

है कि आज एक तारीख हो गया, जरूर एकाऊंट में आ गया होगा । एकाऊंट को लोग चेक करते हैं कि हमारा पैसा आया है या नहीं, लेकिन वो किसान एक साल इन्तजार करेंगे तो उनको एक लाख का कभी 2 हजार, 4 हजार रू0 करके मिलेगा तो क्या होता है उन किसानों का, उनके घर के बाल-बच्चों का कैसे भरण-पोषण होता होगा, वे क्या खाते होंगे, यह आज सोचने की जरूरत है । आपको मंथन करना पड़ेगा, इसमें गवर्नमेंट को इसमें आगे आना चाहिए । चीनी मिल के थ्रु वन टाईम पेमेंट किसानों को कराना पड़ेगा और कराना चाहिए, नहीं तो सभी का तनख्वाह चाहे वह विधायक हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, एम0एल0ए0 हो, सभी का तनख्वाह स्टॉलमेंट में कर दीजिए तो उनको लगेगा, उनको बुझायेगा, उनको तरीका पता चलेगा कि स्टॉलमेंट में पैसा मिलने से कैसे काम चलता है । सभी लोगों का सब तरह का काम होता है लेकिन किसानों का काम सिर्फ अन्न बेचकर के और अनाज बेचकर ही आता है लेकिन उनको कहीं नहीं बख्सा जा रहा है । चाहे किसान वह सुगर केन मिल में अपना केन देता है तो उसका भी पैसा उनको स्टॉलमेंट में मिलेगा । अगर किसान धान की खेती करते हैं, गेहूँ की खेती करते हैं तो उसका पैक्स खरीदता नहीं है, इसका आंकड़ा मंगाईए कि कितना परसेंट खरीददारी कॉअपरेटिव के माध्यम से खरीदा गया है । जब कॉअपरेटिव में धान खरीद होती है तो लोग बोलते हैं कि धान काटिए, दो महीना सुखाईए तब धान का आपका भुगतान किया जायेगा क्योंकि उसमें मोयास्चर होता है । जब मोयास्चर सुखेगा तब धान का जो भी भुगतान होगा, किया जायेगा । मैं माननीय सभापति महोदय, सरकार से जानना चाहता हूँ कि जो गरीब उस धान पर आश्रित किसान रहता है और उसका टुक-टुक नजर होता है, धान कटेगा और हम अपने घर में ले जायेंगे अपने बच्चों का पेट भरेंगे । क्या वह दो महीना धान काटने के बाद इन्तजार कर सकता है । नहीं हुजूर, उसमें भी दलाली होती है । वह किसान जो धान काटता है, उससे दलाल उसी दिन खेत में खरीद लेते हैं, उसको स्टॉक करते हैं और उसको अलग-अलग नामों पर पैक्स के माध्यम से धान सरकार के पास बेचा जाता है । बीच का रूपया कहां जाता है, इसका हिसाब सरकार को देना होगा । बिहार की जनता आपसे पूछ रही है कि यह पैसा कहां जाता है, किसको मिलता है?

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : अब आप समाप्त करें ।

श्री अमित कुमार : लगता है कि इन लोगों को कमीशन मिलता है और हमलोगों को नहीं मिलता है, इसलिए ये लोग बहुत खुश हैं, इसीलिए बता रही है । रोड की जो स्थिति है, आप हमारे यहां कहीं भी चले जाईए, किसी भी क्षेत्र में चले जाईए, मैं

चाहूँगा कि आप एक कमिटी बनाकर भेज दीजिए, आपको लगेगा, हमलोगों को शर्म आता है कि हमलोग किस हिसाब से विधान सभा में बैठते हैं और क्यों बैठ रहे हैं ? जब हम अपनी जनता का काम, अपने लोगों का काम नहीं करा पा रहे हैं तो क्या स्थिति होगा, इसपर हमलोगों को शर्म आता है । सभापति महोदय, आप चलिए, कमिटी भेजिए, दो साल हो गया, बाढ़ आये हुए और अभी तक एक भी सड़क, एक ट्रैक्टर गिट्टी कहीं भी नहीं बिछाया गया है । जो स्थिति हमारे क्षेत्र की है, हमलोग सुदूर बोर्डर से आते हैं, आप समझ सकते हैं कि हमारा गरीब इलाका है, इसलिए सरकार को इसपर ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा सभापति महोदय कि कैसे लोगों का काम हो । विधान सभा में लोग बोलते हैं, हमने गैर-सरकारी संकल्प पढ़ा, हमने दो-दो संकल्प पढ़ा है लेकिन शर्म की बात है कि हमारे माननीय मंत्री आज सांसद बन गये हैं, उन्होंने जवाब दिया कि डी0पी0आर0 बन रहा है । आखिर किस दुनिया में डी0पी0आर0 बनता है, हमको भी नहीं पता है । डी0पी0आर0 बन रहा है, एक भी काम आज तक सुचारू रूप से नहीं हो रहा है । छोड़िए मंत्री जी की बात, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को सीतामढ़ी में पत्र दिया, दो चार काम कर दिया । एक साल बाद फिर से मीटिंग हुआ मुजफ्फरपुर में, उस समय हमलोगों को बताया गया कि डी0पी0आर0 बन रहा है .....

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : अब समाप्त करिए ।

श्री अमित कुमार : महोदय, अब एक लाईन । हमलोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी गुहार लगाये, अब तीन साल बीतने को है और यह शर्म की बात है, फिर हमलोगों को जवाब मिल रहा है कि डी0पी0आर0 बन रहा है तो लगता है कि बिहार में एक अलग सिस्टम बनाया गया है, जो कहीं विदेश से डी0पी0आर0 बनकर आता है, जिसमें तीन-चार साल लगेगा । हमलोग अब चार साल के बाद विधान सभा से बाहर जायेंगे, फिर अगले बार आयेंगे तो फिर डी0पी0आर0 बनेगा । इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि सरकार को जगाईए और सरकार गरीबों का शोषण करना बन्द करे । नहीं तो जनता खड़ी है, जनता जवाब देगी । हवा में मत बहें, इस बार मोदी जी का हवा नहीं चलेगा, जनता बिहार का हवा मांगेगी । धन्यवाद ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : माननीय सदस्य श्री बशिष्ठ सिंह, आपको 10 मिनट का समय है ।

श्री बशिष्ठ सिंह : सभापति महोदय, 12 फरवरी, 2019 को जो बजट पेश हुआ, उस बजट के पक्ष में, वाद-विवाद में अपना पक्ष रखने के लिए सत्ता पक्ष की तरफ से हमलोगों को बोलने का समय मिला है, मैं आसन का आभार प्रकट करता हूँ और

हम अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय का भी आभार प्रकट करता हूँ ।

महोदय, अभी विपक्ष के नेता आदरणीय सिद्दिकी साहेब बोल रहे थे कि बजट कितना का बढ़ा और कितना रिफंड हुआ । महोदय, जब बजट बनेगा ही नहीं, पैसा रहेगा ही नहीं तो काम कैसे होगा ? अगर पैसा ज्यादा रहेगा, काम अधिक करेंगे और अगर कुछ बच जायेगा तो रिफंड करेंगे । लेकिन जब पैसा रहेगा नहीं तो फिर काम कैसे होगा और फिर पैसा लौटने की बात कहां है ? हमें याद है, 2005 की पहले की सरकार की बात याद है, 24हजार करोड़ रू0 का बजट होता था और आज हमारी सरकार के द्वारा 2 लाख 501 करोड़ रू0 का बजट पेश हुआ है और बिहार का विकास का दर 11.3 है जो देश के अन्य राज्यों से ज्यादा है । इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार प्रगति के रास्ते पर जा रहा है और बिहार भारत का रूह कहलाने वाला बिहार फिर एक बार भारत का रूह कहलायेगा, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है । महोदय, शिक्षा के सवाल पर माननीय सदस्य बोल रहे थे, शिक्षा के सवाल पर बिहार में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है । गरीबों की बच्चियां पढ़ने नहीं जाती थी विद्यालय में, हमलोग जब मैट्रिक में पढ़ते थे तो क्लास में 50-55 बच्चे होते थे तो 10 से 15 बच्चियां होती थी लेकिन आज जब हम अपने क्षेत्र में विद्यालय भ्रमण में जाते हैं तो देखते हैं कि बच्चों से ज्यादा संख्या बच्चियों की विद्यालय में है । क्या नहीं काम किया गया महिलाओं के लिए, शिक्षा के सवाल पर कई उल्लेखनिय काम हुये हैं और सबसे बड़ी बात है कि देश की सरकार जी0एस0टी0 लागू करने की बात हुई थी तो उस समय मुख्यमंत्री जी महागठबंधन में थे और उस समय भी उन्होंने कहा था कि अगर जी0एस0टी0 लागू होगा तो देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को कि जब जी0एस0टी0 बिहार में लगा और देश में लगा तो आज अन्य देशों में महंगाई बढ़ा है लेकिन हिन्दुस्तान में जी0एस0टी0 लगने के बाद महंगाई घटा है, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ । महोदय, आज बिहार ऐसा राज्य है, जहां अन्य राज्यों से ज्यादा सरकारी विद्यालयों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं ।

..... क्रमशः .....

टर्न-8/शंभु/02.07.19

श्री वशिष्ठ सिंह : क्रमशः.....मात्र 5 परसेंट बच्चे निजी विद्यालय में जाते हैं बिहार के और 88.7 परसेंट बच्चे आज भी सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं । हम मानते हैं कि

इसमें अभी और सुधार करने की जरूरत है, उसको सुधारने में लगे हुए हैं । जिसका नतीजा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने गरीब बच्चों को, किसान के बच्चों को, मजदूर के बच्चों को पढ़ने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लागू किया है । महोदय, इतना ही नहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 12.5 परसेंट बच्चे रोड पर रहते थे, आज मात्र 1 परसेंट बच्चे बाहर रह गये हैं बाकी स्कूल जाते हैं । महोदय, शिक्षा के सवाल पर बात करें, स्वास्थ्य के सवाल पर बात करें तो आज बिहार में 11 मेडिकल कॉलेज नये बन रहे हैं, स्वीकृत हुए हैं । कहां था 15 साल पहले ? कृष्ण बाबू जब मुख्यमंत्री थे उसके बाद मेडिकल कॉलेज की स्थापना नहीं हुई थी, लेकिन आज 11 मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है और मेडिकल कॉलेज के साथ-साथ जब विपक्ष की सरकार थी तो हम लोग भी जाते थे अस्पताल में जनता के हित में भलाई के लिए तो अस्पताल में न सुई मिलता था, न रूई मिलता था, लेकिन आज चले जाइये, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जाइयेगा तो कम से कम 50 से 100 व्यक्ति प्रतिदिन अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं । जिला में जाइयेगा तो 100 से ज्यादा भी लोग जाते हैं इलाज कराने के लिए और चमकी बुखार की जो बात कर रहे हैं । महोदय, मैं आना चाहता हूँ चमकी बुखार की जो बात करते हैं चमकी बुखार के सवाल पर उन गरीब बच्चों और परिवारों का आँसू पोछने के लिए केन्द्र सरकार के मंत्री गये, मुख्यमंत्री गये, लेकिन विपक्ष के नेता आज तक उन गरीबों का आँसू पोछने के लिए, उनका हाल चाल जानने के लिए नहीं गये । हम तो विपक्ष के लोगों से पूछना चाहते हैं कि कहां हैं विपक्ष के नेता ? जो आज तक गुम हैं इनका पता लगाया जाय । एक दिन नहीं गये और विधान परिषद् की जो नेत्री हैं विपक्ष में वह भी उन लोगों का दर्द सुनने के लिए नहीं गयी । हम जानना चाहते हैं । बात करते हैं नैतिकता की, किस नैतिकता की बात करते हैं क्या था ऊर्जा विभाग में, ऊर्जा विभाग में कुछ नहीं था बिजली कहीं नहीं थी, तार-पोल कहीं नहीं था । जो थोड़ा सा तार था वह भी काटकर ले भागते थे, लेकिन आज बिजली 24 घंटा में 23 घंटा, 22 घंटा ग्रामीण इलाकों में मिल रहा है। अब लालटेन का युग खत्म हो गया, अब लालटेन युग की कोई जरूरत नहीं है । हम तो विपक्ष के सभी माननीय से कहना चाहते हैं कि आपलोग जो अपना पहचान चुनाव चिन्ह लालटेन है उसको बदलकर कोई दूसरा व्यवस्था कर लीजिए । अब बिहार में लालटेन का युग समाप्त हो चुका है, अब लालटेन के युग की जरूरत नहीं है । महोदय, इतना ही नहीं मैं सरकार की उपलब्धि बताता हूँ 60 वर्ष से उपर के जो भी गरीब हैं ए0पी0एल0 हो, बी0पी0एल0 हो- पहले बी0पी0एल0 के लोगों को वृद्धाजन पेंशन मिलता था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बिहार में जो गरीब हैं,

मजदूर हैं, किसान हैं, अल्पसंख्यक हैं, अतिपिछड़ा हैं हर वर्ग के 60 वर्ष से ज्यादा उम्र वालों को 400 रू0 प्रतिमाह वृद्धाजन पेंशन देने का घोषणा किया है और उसका काम शुरू हो गया है । जो 80 वर्ष से ज्यादा के हैं उनको 500 रू0 देने की योजना शुरू की गयी है । इसपर 4800 करोड़ रूपये खर्च आ रहा है । यह राज्य सरकार ने व्यवस्था बनायी है । किसकी बात करें हमलोग अगर उससे आगे चलते हैं तो आर0जे0डी0 के समय में लालटेन का जमाना था और कांग्रेस के समय में लालटेन का जमाना था । महोदय, अब एल0इ0डी0 बल्ब जल रहा है और कांग्रेस के समय में एल0इ0डी0 बल्ब 350 रू0 में एक बल्ब मिलता था और आज 60 रू0, 65 रू0 में एल0इ0डी0 बल्ब मिल रहा है । यह हमारी सरकार की देन है, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ । सबसे बड़ी बात मैं बिहार राज्य की बताना चाहता हूँ देश में पहला राज्य है बिहार जिसके मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी ने लोक शिकायत निवारण कानून लाकर के गरीबों की समस्या का निदान करने के लिए कानून बनाया और उसको अधिकार भी देने का काम किया है । इसमें पहला राज्य बिहार है । आज लोगों को अफसर के पीछे नहीं घूमना पड़ता है, बल्कि आवेदन देने के बाद समस्या का निदान हो जाता है । यह सरकार ने काम किया है। महोदय, इतना ही नहीं हम आज देख रहे थे हमलोगों का भी तारांकित क्वेश्चन था, विपक्ष के लोग अभी आराम से बैठकर इस हाऊस में वाद-विवाद कर रहे हैं, लेकिन जनहित में सभी विधायक ने 243 विधायक की जब समस्या थी उसपर हाऊस में हमलोग बहस करते तब उसका निराकरण होता और उस समय विपक्ष के लोगों ने हंगामा करके, वेल में जाकर के सारे क्वेश्चन को डिस्टर्ब करने का काम किया है । इन लोगों को जनहित से कोई लेना-देना नहीं है, बिहार के गरीबों की सेवा से कोई मतलब नहीं है, केवल अपना चेहरा चमकाने के लिए जब समय था तो उस समय पर चले गये और सदन को डिस्टर्ब करने का काम किया और अभी आराम से बैठकर सुन रहे हैं । इनको शर्म आनी चाहिए सबका क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन को डिस्टर्ब किया गया । हम विपक्ष से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप भी जनप्रतिनिधि हैं, हम भी जनप्रतिनिधि हैं आपका कार्य जनता के हित में होना चाहिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं । हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है विधि-व्यवस्था को सुदृढ़ करना साथ ही साथ कानून का राज स्थापित करना और भयमुक्त समाज बनाने की हमारी प्राथमिकता है । उसी की देन है, हमारे एक महोदय आज बोल रहे थे हिन्दू, मुस्लिम पाकिस्तान की चर्चा कर रहे थे । महोदय, हम बिहार की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात नहीं करते हैं । यह बिहार है और यहां मुर्हरम और दशहरा एक दिन हुआ और कहीं कोई

बाल बांका नहीं हुआ । यह बिहार है और इस बिहार का नेतृत्व नीतीश कुमार और मोदी जी करते हैं यह मैं बताना चाहता हूँ । जहां सामाजिक न्याय की बात हो और जहां सामाजिक सौहार्द्र हो, सामाजिक भावना को कोई ठेस नहीं पहुंचे वैसा यह बिहार है । महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं स्वास्थ्य विभाग के सवाल पर ये लोग मंत्री जी से इस्तीफा मांग रहे हैं ये नाटक नहीं है तो और क्या है ? एक दिन नहीं गये उन गरीबों के दरवाजे पर और आज इस्तीफा मांग रहे हैं । जब मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया, स्वास्थ्य मंत्री जी ने जवाब दिया और जो घटना हुई उससे सबलोग लोगों को कष्ट हुआ, परेशानी हुआ, लेकिन उसपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, उसपर ठोस डिसिजन होना चाहिए और मिलजुलकर होना चाहिए तब जाकर अच्छा निर्णय हो सकता है, तब बिहार के हित में हो सकता है । इसलिए महोदय, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए हम अपने माननीय उप मुख्यमंत्री मोदी जी से कहना चाहते हैं कि उप मुख्यमंत्री महोदय जी जी0एस0टी0 लागू हुआ बिहार को लाभ हुआ, सबकुछ हुआ । हम आपसे एक अपील करना चाहते हैं मेरा छोटा सा सुझाव है कि बैंक की शाखा को बढ़ाया जाय । मेरे विधान सभा क्षेत्र में करगहर 20 पंचायत का ब्लॉक है और वहां पर एक पंजाब नेशनल बैंक, एक मध्य बिहार ग्रामीण बैंक है, हम मांग करना चाहते हैं कि सारा पैसा जो जा रहा है, बैंकों के माध्यम से जा रहा है, एक शाखा करगहर में खोला जाय । हमारा यह आग्रह है । एक बराही बाजार है जहां 5 पंचायत के लोग जाते हैं वहां भी एक शाखा खोला जाय । इन्हीं चन्द शब्दों के साथ आसन का आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ । जयहिन्द ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : माननीय सदस्य श्री महबूब आलम, आपका समय 3 मिनट।

श्री महबूब आलम : सभापति महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, मुझे समय मिलना चाहिए। महोदय, सत्तापक्ष के लोग सुशासन, स्वास्थ्य, चिकित्सा और बिहार विकास के नाम पर जो इतनी दहाड़ मार रहे हैं तो मैं इन लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछली ही बार इस सदन में इनके एक मंत्री को विपक्ष के दबाव पर इस्तीफा देना पड़ा था । मुजप्फरपुर बालिका गृह कांड के 40 बच्चियों की मौत, बलात्कार, हत्या पर इन्हें शर्म नहीं है । महोदय, गीता कुमारी की हत्या हो गयी और एक स्नेहा मुंगेर की जिसकी सीवान में हत्या और बलात्कार हो गया उनको छिपाने की ये कोशिश कर रहे हैं । महोदय, आप 1 तारीख का दैनिक भास्कर देख लीजिए- अपराध बेधड़क, बेखौफ, बेलगाम । महोदय, सिर्फ पटना जिला में जून में एक महीना में 30 हत्या, 33 लूट, 5 डकैती का रिपोर्ट है । इनके बावजूद भी इनको शर्म नहीं आती । महोदय, ग्रामीण विकास का हाल देख लीजिए विकास के अभाव

में बिहार के ग्रामीणों को बाहर पलायन करना पड़ता है जिसकी परिणति हुई कि पिछले दिनों बिहार के 15 मजदूर जिसमें 12 बलरामपुर क्षेत्र के जिसमें 4 बच्चे, 3 किशोर की दर्दनाक मौत हो गयी ।

क्रमशः

टर्न-9/ज्योति/02-07-2019

क्रमशः

श्री महबूब आलम : और इस दर्दनाक मौत पर संवेदना प्रकट करने की जगह माननीय मुख्यमंत्री सिर्फ दो दो लाख रुपये के मुआवजा की घोषणा करते हैं । मैं आग्रह करुंगा कि माननीय मुख्यमंत्री का दौरा हो और उन परिवारों से मिल करके, उनके आने वाले जीवन यापन के लिए उचित व्यवस्था करे, सरकारी नौकरी का इंतजाम करे और 10 -10 लाख रुपया मुआवजा देने की बात करें। शिक्षा की व्यवस्था के बारे में अक्सर बोलता हूँ कि नीतीश कुमार जी को आने वाली पीढ़ी इस बात के लिए याद करेगी कि शिक्षा को इन्होंने बर्बाद कर दिया । बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीनुमा बिल्डिंग बन रही है लेकिन टीचर नहीं है, कॉलेज में टीचर नहीं है । हमारे कटिहार के तारकिशोर जी को खराब लगता होगा । कटिहार डी.एस. कॉलेज जो कटिहार बिहार, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के जिसमें अफ्रिका के स्टूडेंट्स आकर पढ़ते थे उसकी मरणासन्न स्थिति हो गयी है । बारसोई अनुंमंडल के आर.डी.एस. कॉलेज में दो स्टाफ एक क्लर्क, एक टीचर से वह कौलेज चलता है । शिक्षा बर्बाद हो गयी है । उच्च शिक्षा की बात अगर करें तो चालीस साल से इन्होंने वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत दो पीढ़ी की जिन्दगी बर्बाद कर दी और मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि 15 साल से आप हैं तो आप बोलते हैं कि कौंग्रेसियों से जाकर पूछो, कॉंग्रेसी ने बदहाल किया इसलिए तो आपको लाए और जब अपराध की बात होती है तो ये लोग बोलते हैं कि 15 साल में क्या था तो वह 15 साल भूल गए लोग और 15 साल के बाद यह 15 साल पूरा होने जा रहा है तो आपको इसतरह से कहने का क्या मतलब है ? महोदय, स्वास्थ्य की बात मैं करता हूँ । कोई इलाज नहीं । स्वास्थ्य को तो आपने देख लिया कि किसतरह से मुजफ्फरपुर में 200 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई और उन बच्चों की मौत पर भी हमारे विधायक जी दहाड़ रहे हैं । यह दहाड़ कैसे आता है, ये ताकत कैसे मिलती है, यह शक्ति कैसे मिलती है । यह मौब लिंचिंग करने वालों की दोस्ती से ताकत मिलती है । इस वक्त उन्हें संवेदना प्रकट करनी चाहिए और मैं बता

रहा हूं कि एक मंत्री ने इस्तीफा दिया और दूसरा मंत्री लाईन पर है । इनको माफी मांगनी चाहिए और बिहार की जनता से माफी मांग कर बच्चों के प्रति संवेदना प्रकट करनी चाहिए । मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ । बारसोई अनुमंडल में बारसोई एक पी.एच.सी. है, उस पी.एच.सी. में 2018 से एक भी डौक्टर नहीं, एक भी प्रभारी नहीं है उस पी.एच.सी. के तहत 29 स्वास्थ्य हेल्थ सेंटर और 4 एडीशनल पी.एच.सी. है तो वहॉ कैसे सरकार की स्वास्थ्य संबंधी परियोजना चलती है । ये लोग इसीतरह का जवाब देंगे । किसानों के लिए कोई बात नहीं है । बार बार माननीय मुख्यमंत्री से और माननीय उप मुख्यमंत्री से सुनता हूँ, अखबारों में बयान आता है कि बटाईदारों के लिए इंतजाम होगा और उनके फसलों की क्षतिपूर्ति आजतक नहीं हुई और आज बटाईदारों का स्वरुप बदल गया है । बटाईदारी लोग करते हैं और ये ठेका प्रणाली लागू करते हैं इसलिए महोदय, कोई सिस्टेम कुछ नहीं , सत्ता के नशे में चूर हैं ये और इनके सत्ता का नशा एक दिन टूटेगा और हम विपक्षी पूरी चट्टानी एकता से जवाब देंगे और बिहार की जनता जवाब देगी । महोदय, मैं आग्रह करता हूँ कि चार घंटे की बहस में हम भाकपा माले वाले सिद्दत से जनता के सवालों को लेकर आपके पास आते हैं तो मौका हमें मिलना चाहिए । ग्रामीण कार्य विभाग की बात मैं करता हूं । हमारे मंत्री जी शैलेश जी गए थे 2016 से 2017 तक जो सड़के बर्बाद हो गयी बलरामपुर में, सीमांचल में वह सड़के अभी तक नहीं बनी । बारसोई गुमटी इमादपुर, कदम्बा, जिसबानी से होकर तेलपा तक की जो 45 कि.मी. की ग्रामीण विकास विभाग की सड़क है जो कम से कम चार लाख जनता के आवागमन की एक मात्र लिंक लाईन है आजतक वह सड़क बनी नहीं, वह सड़क गढ्ढे में तब्दील होकर दलदल में तब्दील हो गयी है। हमारे ग्रामीण विकास मंत्री गए थे तेलपा टू बलरामपुर सड़क तो उस सड़क में 6 महीने पहले से बना हुआ पुल ध्वस्त हो गया । मेरे सवालों का सरकार जवाब दे और विकास का ढोल पीटना बंद करे ।

डा0 रामानुज प्रसाद : सभापति महोदय, 2019-20 के बजट आकलन के विरोध में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । एक चीज कहना चाहता हूँ माननीय वित्त मंत्री जी के भाषण इनके किताब को पढ़ने से शुरुआती दौर में ही जो इन्होंने चर्चा करी है । एक चीज लिखा है माननीय वित्त मंत्री जी ने What we think today India thinks tomorrow यहीं से शुरु करना चाहता हूँ सभापति महोदय, क्या इंडिया के जो हमारे अन्य राज्य हैं, देश के जो अन्य

राज्य हैं, हम बिहार के लोगों से हमारे वित्तीय प्रबंधन से, हमारे काम काज से यही सीखते हैं कि हमने अपने बच्चों को गुरबत के रोग से मार दिया । बिहार जो पहले सोचता है देश के लोग बाद में सोचते हैं तो बिहार से देश के अन्य राज्य यही सीखेंगे कि गुरबत की बीमारी से बिहार कैसे मारा, हम भी अपने राज्य के बच्चों को गुरबत के रोग से वैसे ही मारेंगे । सभापति महोदय, सही कह रहे थे हमारे नेता, माननीय नेता सिद्दिकी साहेब कि रंग रोगन वाली सरकार है, प्रचार वाली सरकार है, चाहे राज्य में बैठी हो या केन्द्र में बैठी हो । जो बातें की गयी हैं सुशासन, भ्रष्टाचार, अपराध पर जीरो टौलरेंस । सामाजिक सुधार आन्दोलन, मुख्यमंत्री के सात निश्चय । इन्हीं विषयों पर केन्द्रित होकर मैं आज बोलना चाहता हूँ । सुशासन की बात की जाती रही है निश्चित तौर पर सरकार के मुखिया का नाम ही सुशासन बाबू रख दिया गया है लेकिन सुशासन का आलम जो है कि राज्य का डी.जी.पी. कह रहे हैं कि लोग, हमारे महकमा के लोग हमारे पीछे पड़े हैं, साजिश हो रही है । हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है और अंजाम तक मामलों को नहीं पहुंचने दिया जा रहा है । माननीय मुख्यमंत्री जी के मना करने के बाद कि भाषण आप कर रहे हैं दुबारे उनकी अभिव्यक्ति ऐसी हुई है । आखिर वह कौन व्यक्ति है, सरकार में बैठा हुआ वह कौन सख्सियत है जो डी.जी. पी. को काम नहीं करने दे रहा है और बिहार क्राइम से कराह रहा है । बिहार क्राइम से कराह रहा है और डी.जी.पी. रो रहे हैं और फिर हम कहते हैं कि हम सुशासन बाबू के राज्य में रह रहे हैं । हम कहना चाहते हैं कि कहाँ गया जीरो टौलरेंस की बात, भ्रष्टाचार की बात, अगर करें तो सभी सदस्य सत्ता पक्ष के लोगों हों या विपक्ष के भले वह नहीं कहें या सरकार की तरफ हैं तो न कहें लेकिन कहीं भी किसी भी ब्लौक मुख्यालय, में जिला मुख्यालय में, थानों में, कहीं अगर कोई कह दे कि बिना स्पीड मनी देने के बाद क्या कोई काम हो रहा है । हमलोगों के टेलीफोन का आप भी माननीय सभापति महोदय, आपकी कैपेसिटी जब एम.एल.ए. के रुप में करते होंगे बिहार में जो नौकरशाही जितना बेलगाम हुई है इस राज्य में कोई भी माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी नहीं कह सकते हैं कि हाँ हमारे साथ बेहतर है और आपका खराब होगा । कहाँ जाना चाहते हैं हम? क्या इस पुस्तक में या अपने बजट का आकार – हमारे एक साथी कह रहे थे कि इतने का बजट होता है, सत्ताधारी दल के एक साथी कह रहे थे कि पूर्व में इतने का बजट का आकार था, आज बजट का आकार इतना है । हम आपसे

जानना चाहते हैं कि आप बताओ कि आप जब लौज्ड हुए हो और पहले कितने केन्द्र प्रायोजित योजनाएं चला करती थीं और आज कितनी योजनाएं चल रही हैं । हमारा जो इकोनौमिक रिफौर्म्स है वह वन जी, टू जी, थ्री जी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं तो क्या यह बूम औफ रिफौर्म्स नहीं है क्या? तो आप बूम औफ रिफौर्म्स को इंकार कर रहे हो । हमारा जो संघीय ढांचा है उसमें चलने वाली योजनाओं से मिलने वाली राशि का आकार जोड़ कर आप कह रहे हो, अपने बजट का आकार बता रहे हो और किताब में लब्बोलुआब दे रहो हो । क्रमशः...

टर्न-10/02.07.2019/बिपिन

श्री रामानुज प्रसाद : क्रमशः लेकिन आप बताने का काम करिए कि आपने बिहार में कौन-सा सोर्स ऑफ इन्कम क्रीएट किया है ? आप बताइए कि सोर्स ऑफ इन्कम क्या है आपका ? यह भी इसमें चर्चा का विषय होना चाहिए । हम कहना चाहते हैं सभापति महोदय कि यह निराशाजनक बजट है चाहे आकार इसके जितने हों, चूंकि परिणाम बजट नहीं है यह । परिणाम बजट अगर होता तो हम पूछना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में हैं नहीं और अगर हैं, अपने कार्यालय कक्ष में हों, वित्त मंत्री जी भी उठकर चले गए, वह भी आ जाएं या सुन रहे होंगे तो उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि दो ही महकमा, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन दो महकमा है जिससे किसी भी राज्य राष्ट्र का वर्त्तमान और भविष्य दोनों सुधरता है । हम अपने नागरिक को अगर बेहतर शिक्षा नहीं दे पाते हैं, हम अपने नागरिक को अगर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा नहीं उपलब्ध कराते हैं तो हम अपने लोगों को न बचा सकते हैं, न पढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और हम समझते हैं कि इन दोनों में हमारा राज्य फिसड्डी साबित हो रहा है चाहे हम जितनी बात कर लें कि हम जो सोचते हैं, कल भारत सोचता है । यह हम जानना चाहते हैं कि चाहे स्वास्थ्य पर चर्चा हो रही हो, रोज मीडिया के लोग भी आज के दिनों में दिखा रहे हैं, रोज लोग जा रहे हैं और हमें कहना पड़ता है बड़ी दुःख के साथ कि हमारे प्रधानमंत्री जी खाए-पीए हुए लोगों का, स्वस्थ लोगों का जिनका गाल रामानुज के गाल से भी ज्यादे बड़ा-बड़ा है, पेट हमसे भी ज्यादे निकला हुआ है, उनका गाल पचकवाने रांची तो आ जाते हैं योग कराने, लेकिन 10 मिनट का भी फ्लाइट का समय रांची से मुजफ्फरपुर का नहीं है, वहां जाने की जुर्रत नहीं करते हैं चूंकि यहां चुनाव नहीं है और झारखंड में चुनाव था, या आने वाला है चुनाव तो वहां चले जाते हैं खाए-पीए हुए लोगों का, जो खा-पीकर, सारे देश के जो क्रीम हैं, हमारे जो सोर्स ऑफ इन्कम हैं, जो हमारे मिंस है, उनपर जिनका कब्जा है माइंस पर,

मिनरल्स पर, धन पर, संपत्ति पर, सिस्टम पर, सरकार पर, सब पर जिनका कब्जा है, जो खाकर गाल फुलाए हुए हैं, पेट फुलाए हुए हैं, उनका पेट और गाल पचकवाने प्रधानमंत्री जी आप आते हैं रांची में योग कराने और आप मरते हुए, गुरूवत के रोग से मरते हुए बच्चें को गरीबी के रोग से मरते हुए बच्चों को देखने आने का आपको फुर्सत नहीं मिलता है और आप कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास ? आप हैं, यह मैं स्वीकार सकता हूं कि निश्चित तौर पर आपने गोल पोस्ट बदल दिया । इलेक्शन में गोल पोस्ट बदल कर आपने चुनाव जीतने का काम किया है । सारे लोग जानते हैं कि सेना के नाम पर चुनाव आयोग के कहने के बाद आप वोट मांगते रहे । देश के लिए सीना ऊँचा करने के नाम पर, छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर और लोग मर रहे थे । प्रधानमंत्री जी को शर्म आती है लोकसभा में नहीं, राज्यसभा में । हमारे मुख्यमंत्री जी जाते हैं जब हमारे बच्चे सौ से ज्यादा मर जाते हैं तो 19 दिन के बाद जाते हैं और कहते हैं कि मैं 15 साल के बाद मुजफ्फरपुर गया था इसी सदन में । पहली बार गया 15 साल के बाद, सभापति महोदय, और ऐसे लोग, ऐसे सरकार के वित्त मंत्री अपने किताब में लिखते हैं कि सुशासन है, भ्रष्टाचार-अपराध पर जीरो टॉलरेंस है हमारा । बल्कि मेरा तो अनुभव है कि हमारे माननीय वित्त मंत्री, बड़े भाई सुशील कुमार मोदी जी वित्त मंत्रालय का काम कम, बजट किसी से प्रौसेस होता होगा, देख लेते होंगे, मोनिटरिंग करते होंगे, दिन-रात लालु चालिसा पढ़ने से इनको फुर्सत नहीं है । यहां भी पढ़ते हैं, विदेश में भी पढ़ते हैं । हमलोग इनके साथ विदेश गए थे, वहां भी जहां खोजते थे, एयरोड्रॉम पर हमलोग थे तो इनको कहीं से समाचार मिला तो ये समाचार के सिवाय और कुछ बोलने बताने का हमलोगों को, अपने बड़े भईया को खोजने लगे । देश में भी खोजते हैं विदेश में भी खोजते हैं । ये वित्त मंत्रालय का काम कब देखते हैं ?

अब मैं आना चाहता हूं स्वास्थ्य पर । स्वास्थ्य की जो स्थिति है, यह चर्चा बहुत हो गई है । मैं शिक्षा पर आना चाहता हूं । जो दूसरे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं किसी भी ह्युमैन इंडेक्स डेवलपमेंट में किसी भी कंट्री और स्टेट के लिए राज्य राष्ट्र के लिए जो सबसे इम्पौर्टेंट कंपोनेंट है उसपर मैं आना चाहता हूं । क्या है स्वास्थ्य की स्थिति ? मैं वित्त मंत्री जी से ही शुरू करूंगा । बड़े भाई हैं, जानने का प्रयास करते हैं माननीय वित्त मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी भी मेरे मित्र हैं । पीछे बैठकर सुन रहे हैं । माननीय वित्त मंत्री जी, आप पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं । आप हमें एक चीज बताने का काम करिए कि पटना यूनिवर्सिटी जो आपके जमाने में था और पटना यूनिवर्सिटी में साइंस कॉलेज की जो न सिर्फ हमारा सबसे प्रिमियर और सबसे अच्छा इंस्टिच्युशन है बिहार का, आज भी है, आज भी गरीब के बच्चे वहां आने के लिए

लालायित रहते हैं कि हम पटना यूनिवर्सिटी जाएंगे । अब आपने बिगाड़ा है तो डी.यू. की जे.एन.यू. की बात कर रहे हैं लेकिन अभी तक ख्वाब भी जब हमलोग.....

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): अब आप समाप्त करें ।

श्री रामानुज प्रसाद : तो हमलोग पटना यूनिवर्सिटी आए लेकिन हम जानना चाहते हैं माननीय वित्त मंत्री जी कि पटना यूनिवर्सिटी की स्थिति या जितने फैकल्टी, जितने लेक्चरर, जितने एसोसिएट्स, जितने प्रोफेसर्स उस समय थे, रिसर्च वर्क जो उस समय हो रहा था, आज पटना यूनिवर्सिटी में हो रहा है क्या ? तो जब पटना यूनिवर्सिटी का यह हाल है, साइंस कॉलेज का यह हाल आपने बना दिया, बी.एन. कॉलेज का यह हाल आपने बना दिया तो बिहार के हमारे अन्य यूनिवर्सिटी तो सिर्फ फार्म भरवाओ, परीक्षा लो और कैसे परीक्षा लो, यह भी जगजाहिर है और पास करा दें चूंकि कहीं फैकल्टी नहीं है । एक दिन मैं दौरा पर था । कहीं एम.आई.टी. के टीचर एक मिल गए । मेरे दूर के जानने वाले लोग थे । उन्होंने हमको चाय पर बैठाए और कहने लगे हमलोग क्या पढ़ाएंगे ? आप कानपुर से एम. टेक. करके आए हैं...

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): रामानुज बाबु, अब आप समाप्त करें ।

श्री रामानुज प्रसाद : सभापति महोदय, थोड़ा-सा और समय दीजिए मुझको । हमारे पार्टी का और समय ले लीजिए । हमारे चीफ व्हीप साहब बैठे हुए हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा चाहे इंजीनियरिंग कॉलेजेज हों, हमारे टेक्नोलॉजी कॉलेजेज हों, हमारे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेज हों, शिक्षा की जो हालत है स्कूल से लेकर के, सही कहा एक साथी ने । हमारे साथी कह रहे थे कि नीतीश जी अगर जाने जाएंगे तो सबसे ज्यादे जाने जाएंगे, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में आप याद किए जाइएगा बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी । हम यह कहना चाहते हैं । एक और इम्पॉर्टेंट सवाल है । वोट लेना होगा तो एस.सी./एस.टी. के लोगों के लिए घड़ियाली ऑसू बहाना शुरू करते हैं प्रधानमंत्री जी भी और मुख्यमंत्री जी भी ....

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): अब आप समाप्त करें ।

श्री रामानुज प्रसाद : सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि पॉलिटेक्निक कॉलेजेज जो हैं ए.आई.सी.टी.ई. के व्यवस्था के तहत चलने वाले जो इंस्टिच्युशन हैं, किसी में एस.सी./एस.टी. के बच्चों को आरक्षण नहीं दिए जा रहे हैं । प्रावधान है लेकिन उसमें बेइमानी किया जा रहा है । इस ओर हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं । एक और इम्पॉर्टेंट इशु है और वह है नल-जल योजना । सात निश्चय मुख्यमंत्री जी का, चूंकि ऊपर ही लिखा हुआ है और ऊपर ही में किताब में वर्णित है सात निश्चय

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): अब आप समाप्त करें ।

श्री रामानुज प्रसाद : सभापति महोदय, एक मिनट, सभी सदस्यों का सवाल है और हमारे संजय सरावगी जी, हमलोग प्राक्कलन समिति में हैं, उसके वे सभापति हैं, हमलोग पूरे बिहार का दौरा किए और कहीं मानक के हिसाब से नल-जल योजना में काम नहीं हो रहा है, सिर्फ लूट है और ज्यादातर ठीकेदार नालन्दा के रहने वाले हैं । कोई भी सदस्य उठकर कहे कि नल-जल योजना क्या है ....

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): अब आप समाप्त करें ।

श्री रामानुज प्रसाद : एक मिनट, लेकिन हम अफसोस करना चाहते हैं सभापति महोदय....

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): अब आप समाप्त करें ।

(व्यवधान)

आप समाप्त करिए । आपका रेकर्ड में नहीं जा रहा है । माननीय सदस्य श्री चन्द्रसेन प्रसाद । आप बोलिए ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : माननीय सभापति महोदय, आपने बजट पर चर्चा करने का मौका दिया है इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

धन्यवाद इसलिए महोदय कि आज की जो परिस्थिति है ....क्रमशः

टर्न-11/कृष्ण/02.07.2019

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : (क्रमशः) आज की जो परिस्थिति है, बिहार में न्याय के साथ विकास और विकास के साथ सात निश्चय, पूर्ण शराबंदी, बाल-विवाह, दहेज प्रथा जैसे आंदोलन पर बिहार में न्याय के साथ विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है । महोदय, आज का जो विषय है, हम कहना चाहते हैं, हमारे विरोधी के दल के लोग अपनी बात को रखने का काम किये बजट पर, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं सभापति महोदय, जब महागठबंधन से चुनाव लड़ करके सरकार बनाये थे तो सात निश्चय के बारे में खूब राग अलापते थे कि हर घर नल का जल, हर घर में शौचालय, हर घर में बिजली का कनेक्शन, हर घर के सामने नली-गली, सारी बातें आप ही बोलते थे । आज आपके सामने कौन-सी विपत्ती आ गयी है कि आप हर बात में उल्टा बोलने का काम करते हैं । सभापति महोदय, आज इस बिहार में, माननीय श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सामाजिक क्रांति के साथ बिहार बदलाव की ओर अग्रसर है और वहीं बिहार और देश में प्राकृतिक बदलाव भी आने के संकेत मिले हैं । महोदय, सामाजिक बदलाव, प्राकृतिक बदलाव के संकेत और हस्तक्षेप यह जाहिर

करता है कि इस बिहार में सभी राजनीतिक पार्टियों को, पक्ष-विपक्ष को सही मुद्दों पर आने की जरूरत है ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष महोदय, एक तरह से बिहार के विकास पुरूष आदरणीय नीतीश कुमार जी सबका साथ, सबका विकास के साथ सात निश्चय, शराबबंदी को पूरे तरीके से ले जाने का काम कर रहे हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो बजट लाया गया था और आज उस पर चर्चा हो रही है, उस चर्चा में, जो सामाजिक क्रांति है, जो सात निश्चय है, जो शराबबंदी है, उस पर ध्यान देने की बात है । हम कहना चाहते हैं कि बहुत से हमारे माननीय सदस्य सात निश्चय पर अपनी बात रखने का काम किये, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि हर घर नल का जल, आप कहां के रहनेवाले हैं ? कहां आपने देखा ? क्या कभी आपने हर घर नल का जल आपने सुना था कि हर घर में नल का जल, सात निश्चय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने धरती पर इसे उतारने का काम किया है और 2010 तक हर घर में नल के जल को देने का निश्चय किया है । तो आज पूरे बिहार में आज जो प्राकृतिक संकट और जलवायु में परिवर्त्तन के संकेत मिले हैं, सुखाड़ की स्थितियां हैं, गांव में लोग कहते हैं कि सात निश्चय में अगर नल का जल नहीं होता तो आज जो चापाकल का जल स्तर नीचे चला गया है, उसमें आज निश्चित रूप से हमलोगों को पीने का पानी का चुनौती होता । लेकिन जो नल का जल सात निश्चय से मिला, आज पूरे बिहार में उसकी प्रशंसा हो रही है । आज देश में ऐसा कोई हिस्सा नहीं है, जहां हर घर नल का जल है ।

महोदय, उसी तरह से हर घर में बिजली का कनेक्शन । पहले जिनके घरों में बिजली का कनेक्शन होता था, बिजली जब आती थी तो चर्चा होती थी कि आज बिजली आयी और आज उनके घर में बिजली है । आज बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आज हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया जा रहा है ।

महोदय, नाली-गली । पहले लोग कहते थे कि लोग विधायक जी के यहां जाकर कहते थे कि विधायक जी, नाली चाहिए, गली चाहिए । लेकिन आज नाली और गली सभी के दरवाजे पर जा रहा है, सभी गरीबों के दरवाजे पर जा रहा है । महोदय, महिलाओं का सशक्तिकरण । महिलाओं को तो खुश होना चाहिए, 35 प्रतिशत का आरक्षण सभी नौकरियों में, आज पूरे हिन्दुस्तान में कोई ऐसा राज्य नहीं

है, जहां महिलाओं के लिये 35 प्रतिशत आरक्षण देने का काम किया गया है । इसलिए हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि बिहार में जो परिवर्त्तन आया है, जो सामाजिक परिवर्त्तन की ओर माननीय मुख्यमंत्री जी का ईशारा है, उसके संबंध में हम यह कहना चाहते हैं कि इन्होंने बिहार में शराबबंदी लागू किया, शराबबंदी का असर पूरे बिहार में है । लोग कहते हैं कि होम डिलीवरी होता है । आप बताईये कि होम डिलीवरी कहां पर है ? आप पुलिस को कंप्लेन क्यों नहीं करते हैं ? महोदय, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि बिहार के गरीब-गुरूबा की जो स्थिति है, उसमें शराबबंदी के बाद काफी सुधार हुआ है । लोग अच्छे-अच्छे कपड़े पहनने लगे हैं, लोग खुशहाल हैं, लोगों का घर बनने लगा है और शराबबंदी से पूरा असर हुआ है ।

दहेज प्रथा, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो महारथी थे, महापुरूष थे, वे कल्पना किये थे कि अगर हमारे यहां दहेज-प्रथा पर रोक लगता तो दलितों, शोषितों को न्याय मिलता, इन सब बातों की ओर हमारे महापुरूषों का ध्यान जाया करता था और माननीय मंत्री नीतीश बाबु, कभी-कभी हम सोचते हैं कि ऐसे समय में हमलोगों का जन्म हुआ है जब महापुरूष आदरणीय नीतीश कुमार जी आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं ।

महोदय, हम आप से कहना चाहाते हैं कि हर क्षेत्र में बिहार में परिवर्त्तन आया है और न्याय के साथ विकास की गाड़ी मजबूत हुई है । विकास के सवाल पर लोग कहते हैं, विरोधी दल के उप नेता कह रहे थे कि विधायकों के लिये फ्लैट बन रहा है, आप सब विधायकों को क्या नाराजगी है ? विधायक को फ्लैट में रहना, देखना पसंद नहीं करते हैं ? महोदय, हम कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक से एक काम किये गये हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य चन्द्रसेन जी, आपको एक ही मिनट में समाप्त करना है। इसलिए आपको जो मुख्य बातें कहनी हैं, वह आप कह दीजिये ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, बिहार में काफी परिवर्त्तन हुये हैं । बिहार में पहले बैल से खेती हुआ करता था । अब ट्रैक्टर से नहीं, हार्वेस्टर से खेती होती है और हार्वेस्टर से कटता है । सिंचाई के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने खेतों तक बिजली पहुंचाने का निश्चय किया है और 2010 तक उसको पहुंचाने का लक्ष्य है।

महोदय, सड़क के क्षेत्र में, लोग बोल रहे थे, उनको पता नहीं कि गांवों में सड़कें बन गयी है । हर गांव को, हर टोले को सड़कों से जोड़ने का काम लगभग पूर्ण कर दिया गया है । लेकिन हमारे विरोधी लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि सड़क बन रहे हैं । गांवों में जाकर आंख खोल कर देखिये कि सड़कें

हैं या नहीं, विरोध होता है लोगों से, बिहार के विकास से ईर्ष्या मत की जिये । इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि बिहार में हरेक क्षेत्र में विकास हुआ है, चाहे लॉ एण्ड ऑर्डर का सवाल हो । पहले लोग, जब शाम को 4 बज जाता था तो लोग अपने-अपने घर जाने की तैयारी करने लग जाते थे ।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : आज पूरे बिहार में लोग रातभर घूमते हैं । कोई चिंता नहीं है, सुशासन की सरकार है । शासन अपना काम कर रहा है । इसलिए अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हुये, माननीय मोदी जी और मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को बधाई देते हुये उन्हें धन्यवाद देता हूं । महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मैंने अपनी बातों को रखने का काम किया । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक पर हुये सामान्य विमर्श पर सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री,वित्त विभाग ।

<u>सरकार का उत्तर</u>

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2019-20 का बजट मार्च महीने में सदन के अंदर पेश किया गया था और मैं माननीय सदस्यों को स्मरण कराना चाहूंगा कि मार्च महीने के विधान-मंडल के सत्र में निर्वाचन, गृह, आपदा प्रबंधन मद की पूरी राशि और बाकी मदों का एक तिहाई भाग यानी चार महीने के खर्च की अनुमति प्राप्त की गयी थी । बजट तो पूरे साल का पेश कर दिया गया था । लेकिन आचार-संहिता और चुनाव को ध्यान में रखते हुये चूंकि सत्र छोटा था, इसलिए केवल अप्रील, मई, जून और जुलाई चार महीने के खर्च की अनुमति ली गयी थी और अब ये जो विधान-मंडल का सत्र हो रहा है, इसमें बाकी बचे 8 महीने के खर्च की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को याद कराना चाहूंगा कि जो बजट पेश किया गया है, वह अभी तक का बिहार का सबसे बड़ा बजट है । महोदय, 2 लाख 501 करोड़ रूपये का बजट पेश किया गया है और जिसको योजना व्यय कहते हैं, वह 1 लाख 1 हजार 391 करोड़ का योजना व्यय है । अध्यक्ष महोदय, हमलोगों ने 2005-6 में 22, 23 हजार करोड़ से बजट प्रारंभ किया था और आज यह 9 गुणा, 10 गुणा बढ़कर 2 लाख 501 करोड़ पर पहुंच गया है ।

क्रमश :

टर्न-12/अंजनी/दि0 02.07.19

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री...क्रमशः.... अध्यक्ष महोदय, इस खर्च में, इस बजट में केवल वेतन मद में 51,740 करोड़ रूपया खर्च किया जायेगा, पेंशन के मद में 18,457 करोड़ रूपया और व्याज मद में 10,723 करोड़ रूपया । मैं आंकड़ों के विस्तार में नहीं जाउंगा लेकिन इस बजट में सबसे ज्यादे जो राशि खर्च की जायेगी, वह शिक्षा पर खर्च की जायेगी और यह राशि है वर्ष 2019-20 के लिए 34,798 करोड़ रूपया और अगर आवश्यकता होगी तो हम और भी अधिक राशि के लिए सदन के पास आयेंगे लेकिन शिक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और 34,798 करोड़ रूपया इसपर व्यय होगा । उसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग पर 9,622 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । अभी तक का स्वास्थ्य पर सबसे बड़ा प्रावधान है । सड़क प्रक्षेत्र में, ग्रामीण.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, सड़क प्रक्षेत्र पर पथ निर्माण विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग दोनों मिलाकर 17,923 करोड़ रूपया, करीब 18 हजार करोड़ रूपया केवल हम सड़क प्रक्षेत्र पर खर्च करेंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि जब से बिहार में माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में एन0डी0ए0 की सरकार बनी है वर्ष 2005-06 से लेकर अभी तक अगर हम 2019-20 के बजट को जोड़ लें तो शिक्षा पर कुल मिलाकर 2 लाख 27 हजार करोड़ रूपया खर्च हुआ है और उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय,

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अभी बोलने दीजिए । बोलने दीजिए ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, सड़क प्रक्षेत्र पर ग्रामीण कार्य और पथ निर्माण पर जिन लोगों की 15 साल की सरकार थी, उन्होंने खर्च किया.....

(व्यवधान)

बात तो सुन लीजिए । अध्यक्ष महोदय, 1990-91 से लेकर 2004-05 तक बिहार की सड़कों पर 15 साल में खर्च हुआ, बिहार की सड़कों पर 6 हजार 71 करोड़ रूपया और हमलोगों की सरकार में आने के बाद 13 साल में खर्च हुआ 1 लाख 30 हजार करोड़ रूपया तो कहां 6 हजार 71 करोड़ और कहां 1 लाख 30 हजार करोड़ रूपया ....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, बिजली के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में वर्ष 2005-06 से लेकर अभीतक .....

अध्यक्ष : ललित जी, अब आप सुनिए, अब आप लोगों की बात मानकर ये अपनी सरकार की बात कर रहे हैं । 2005-06 से बता रहे हैं, उसको तो ध्यान से सुनिए।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2005-06 से अभी तक ऊर्जा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में 99,625 करोड़ रूपया यानी लगभग 1 लाख करोड़ रूपया केवल बिजली के क्षेत्र में खर्च हुआ है । अध्यक्ष महोदय, अभी यहां विजेन्द्र बाबू बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी भी बैठे हुए हैं, अभी तो हमने बिहार के हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी का यह निश्चय है कि इस साल के अन्त तक बिहार के हर खेत तक बिजली पहुंचाने का काम करेंगे । एक भी खेत नहीं बचेगा । जो लोग खेती के लिए बिजली चाहते हैं, उनको हर खेत तक बिजली पहुंचायेंगे और 31 दिसम्बर पार नहीं होने देंगे । अध्यक्ष महोदय, अभी तक 1 लाख 03 हजार खेतों तक बिजली पहुंच चुकी है और 31 दिसम्बर तक जो बिजली चाहेंगे औरे बिजली की दर क्या होगी, केवल 75 पैसा प्रति यूनिट और यह बिजली दर कृषि कार्यों के लिए निर्धारित है । अध्यक्ष महोदय, सरकार एक और निर्णय लेने जा रही है, बहुत जल्द उसपर नीतिगत निर्णय हो जायेगा । अब सौर ऊर्जा से सिंचाई की योजना को बहुत जल्द स्वीकृति होगी और 30 हजार से ज्यादा सिंचाई के पंप को सौर ऊर्जा से चलाये जायेंगे । अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का प्रयास होगा कि आनेवाले दिनों में डीजल को हम खत्म कर देंगे खेती से । किसी भी काम के लिए कृषि के अन्दर डीजल का उपयोग न करना पड़े, ऐसी स्थिति आनेवाले दिनों में हम पैदा करेंगे । अध्यक्ष महोदय, इस साल का जो बजट पेश किया गया, उसपर बहुत तरह की टीका-टिप्पणी हो रही है अध्यक्ष महोदय लेकिन मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि क्रिसिल नाम की एक संस्था जो सारे चीजों की रेटिंग करती है, उसने बिहार के बजट के बारे में क्या कहा या बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कहा- क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में कहा- Report States of growth, जनवरी 2019 में देश के सभी राज्यों की अर्थव्यवस्था पर उन्होंने एक रिर्पोट प्रकाशित की है और मैं सदन को बताना चाहूंगा, उस रिपोर्ट के अनुसार और केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार वर्ष 2017-18 में बिहार देश के सबसे ज्यादा विकास दर हासिल करनेवाले राज्यों के अन्दर है । वर्ष 2017-18 में हमने 11.3 प्रतिशत् की विकास दर हासिल की है और पूरे देश में बिहार प्रथम स्थान पर रहा है । अध्यक्ष महोदय, पंजाब का विकास दर 6.2, केरल का 5, आंध्र, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक ये सारे राज्य बिहार के

बाद हैं और बिहार सर्वाधिक विकास दर हासिल करके देश में सबसे ज्यादा विकास दर हासिल करनेवाले राज्यों में शामिल हुआ है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, जो हमने विकास दर हासिल किया है, यह विकास दर रोजगार पैदा करनेवाला विकास दर है । यह हम नहीं कह रहे हैं, ये क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि निर्माण, Construction क्षेत्र, Manufacturing, Trade, Hotel, Transport और दूरसंचार तो बिहार का जो विकास दर है, वह सर्वाधिक रोजगार पैदा करनेवाला विकास दर है ।

...क्रमशः...

टर्न-13/राजेश/2.7.19

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : ... क्रमशः... यह क्रिसिल ने अपने रिर्पोट में कहा है । क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है जो कंज्यूमर प्राईस इनडेक्स है यानि खुदरा मॅहगाई की जो दर है उसमें बिहार देश में सबसे कम मॅहगाई की जो दर है, वह बिहार के अंदर है । अध्यक्ष महोदय, जहॉ केरल में कंज्यूमर प्राईस इनडेक्स है, वह 6 परसेंट है, तमिलनाडु में 4.9 परसेंट है, महाराष्ट्र में 4.1 परसेंट है तो बिहार में केवल मॅहगाई का दर कंज्यूमर प्राईस इनडेक्स केवल 2.7 परसेंट है और महोदय इतना ही नहीं, क्रिसिल ने अपनी रिर्पोट में कहता है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है यानि जिससे राज्य में स्थायी सम्पत्ति का निर्माण होता है, एसेट का निर्माण होता है तो 2015 से 2018 के बीच में बिहार में पूंजीगत परिव्यय यानि सड़क, बिजली, पुल-पुलिया यानि की जो स्थायी सम्पत्ति का निर्माण है उसपर बिहार में कुल व्यय में पूंजीगत व्यय में 21.8 परसेंट खर्च किया है, जबकि केरल में केवल 9 परसेंट, पश्चिम बंगाल में 10.3 परसेंट और महाराष्ट्र में केवल 11.8 परसेंट खर्च किया है । अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो अपनी रिपोर्ट को सार्वजनिक की है-स्टडी ऑफ बजट 17-18 एवं 18-19 के अनुसार जो बिहार के बारे में इन्होंने जो टिप्पणी की है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा.....

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन के वेल में आ गये)

लेकिन बिहार देश के अंदर जो रेवेन्यू है, वह सरप्लस स्टेट के अंदर यह बिहार रेवेन्यू सरप्लस स्टेट में शामिल है महोदय और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार 2008-09 से बिहार लगातार रेवेन्यू सरप्लस राज्य बना हुआ है ।

2018-19 में 21 हजार 311 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस हमने हासिल किया है, जबकि आन्ध्रप्रदेश, हरियाणा, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब ये रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट हैं, इन राज्यों को वेतन, पेंशन के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है और अध्यक्ष महोदय मैं बताना चाहूंगा कि जो वित्त आयोग की रिर्पोट आयी है, 14वीं वित्त आयोग की रिपोर्ट उसमें रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट आन्ध्रप्रदेश, हरियाणा, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान को एक लाख 94 हजार करोड़ ये रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट के रुप में इन राज्यों को ग्रांट देने का काम किया है । अध्यक्ष महोदय, हमने बेहतर वित्तीय प्रबंधन किया, इसलिए हम इस ग्रांट से वंचित रह गये लेकिन जिन राज्यों के अंदर बेहतर वित्तीय प्रबंधन नहीं था उनको 14वीं वित्त आयोग ने एक लाख 94 हजार करोड़ रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के रुप में देने का काम किया है, आन्ध्रप्रदेश को 22113 करोड़, केरल 9519 करोड़, पश्चिम बंगाल को 11707 करोड़ और यह रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के रुप में दिया गया है । अध्यक्ष महोदय, हमने कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और मैं सदन को बताना चाहूंगा कि जब 2018-19 में राज्य के 25 जिलों के 280 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया और मैं सदन को बताना चाहूंगा कि राज्य के 14 लाख 18 हजार किसानों को 934 करोड़ रुपया कृषि इनपुट अनुदान के रुप में उनके खाते में देने का काम किया गया है, उसी प्रकार डीजल अनुदान खरीफ में और 15 लाख 66 हजार किसानों को 195 करोड़ रुपया वितरित किया गया है । अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना जिसे हरेक किसान के खाते में छः हजार रुपया दिया जायेगा, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि 8 लाख, 77 हजार 731 किसानों के खाते में 221 करोड़ रुपया ट्रान्सफर किया जा चुका है और कुल मिला करके देखेंगे अध्यक्ष महोदय तो वर्ष 2018-19 में 47 लाख 16 हजार किसानों के खाते में 1864 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने उन्हें देने का काम किया है । अध्यक्ष महोदय, अभी बिहार की सड़कों की चर्चा हो रही थी तो मैं सदन को बताना चाहूंगा कि अब राज्य सरकार ने सभी सड़कों की मरम्मति कराने का निर्णय लिया है और हमने ओ0पी0आर0एम0सी0 के तहत सड़कों के मेनटेनेंस की नीति बनायी है और जो पथ निर्माण विभाग है, उस पथ निर्माण विभाग ने 13 हजार 64 किलोमीटर सड़कों को सात साल के लिए उनके मेनटेनेंस के लिए निर्णय लिया है, उसका टेंडर भी हो चुका है और हम 13 हजार 64 किलोमीटर सड़कों की मरम्मति और उसके अनुरक्षण के लिए 6654 करोड़ रुपया हम केवल पथों के अनुरक्षण पर हम खर्च करेंगे । उसी प्रकार जो ग्रामीण सड़कें हैं उसके भी रख-रखाव का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है और मैं सदन को बताना चाहूंगा कि 2019-20 में हम

18 हजार किलोमीटर सड़कों के मेनटेनेंस के लिए टेंडर करने जा रहे हैं । जिसमें से 6500 किलोमीटर का टेंडर पूरा हो चुका है और इस साल 2019-20 में हम 2500 करोड़ रुपया ग्रामीण सड़कों की मेनटेनेंस पर मरम्मति पर खर्च करेंगे । अध्यक्ष महोदय, बिहार के अंदर जो गरीब हैं, विधवा हैं, दिव्यांग हैं, जो वृद्धजन हैं, हमारी सरकार 63 लाख 87 हजार वृद्ध, दिव्यांग और जो विधवा हैं उनको पेंशन देने का काम कर रहे हैं और 2018-19 में लगभग तीन हजार करोड़ हमने बिहार के 63 लाख 87 हजार वृद्ध, दिव्यांग और विधवाओं को देने का काम किया है । अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना जिसको हमारी सरकार ने बिहार में देने का काम किया है, अब एक भी वृद्ध बिहार में नहीं बचेगा जो पेंशन से वंचित रह जाय, 60 साल से उपर के सभी वृद्ध चाहे वह ए0पी0एल0 हो या बी0पी0एल0 हों, उन सबों को 400 रुपया पेंशन मिलेगा और सदन को मैं कहना चाहूंगा कि 1 जुलाई तक 5 लाख आवेदन आ चुके हैं और अभी तक 1 लाख 35 हजार 928 वृद्धजनों को अप्रैल और मई महीने के पेंशन का भुगतान किया जा चुका है तो जितने भी लोग आगे आयेंगे 60 साल के उपर के उन सभी लोगों को अध्यक्ष महोदय और राज्य सरकार की ओर से 400 रुपये का पेंशन दिया जायेगा । अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का यह निश्चय है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नली पक्की निश्चय योजना है उसके बार में मैं सदन को बताना चाहूंगा ।

क्रमशः

टर्न-14/सत्येन्द्र/ 2-7-19

(व्यवधान जारी)

श्री सुशील कुमार मोदी,उपमुख्यमंत्री(क्रमशः): महोदय, मैं सदन को बतलाना चाहूंगा कि दिसम्बर, 2019 तक बिहार के हर घर में हम नल से जल पहुंचाने का जो संकल्प लिया है, एक भी घर नहीं बचेगा इस बिहार के अन्दर, जहां नल से जल नहीं पहुंचायेंगे और 2018-19 के लिए अबतक कुल मिलाकर 12 हजार 500 करोड़ रू0 सीधे ग्राम पंचायतों को राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है । अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय विधायकों से भी आग्रह करूंगा कि अगर नल जल योजना में कहीं गड़बड़ी है, अगर सड़क योजना में कहीं गड़बड़ी है तो आप लिखकर दें, आप शिकायत करें लेकिन हमारा संकल्प है सरकार का कि हर घर तक हम जल पहुंचाने का काम पाईप वाटर सप्लाई से करेंगे । अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है इस बात की कि बिहार की योजना से प्रेरित होकर भारत सरकार ने भी यह निश्चय

किया है कि वर्ष 2024 तक इस देश के हर घर में पाईप से पानी पहुंचाने का काम करेंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह भी बतलाना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री दोनों का सपना है, हर घर में शौचालय बनना और मैं सदन को बताना चाहूंगा कि अभी तक बिहार में 1 करोड़ 11लाख शौचालय का निर्माण किया जा चुका है और लगभग 100 प्रतिशत हमलोगों ने शौचालय बनाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है और जो थोड़े बहुत बचे होंगे लोग, माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है कि 15 अगस्त, 2019 तक एक भी घर नहीं बचेगा जिसके घर में शौचालय नहीं होगा और 02 अक्टूबर 2019 को जब पूरा देश खूले में शौच से मुक्त होगा तो बिहार भी पीछे नहीं रहेगा और मैं सभी माननीय विधायकों से आग्रह करूंगा कि लोग शौचालय में जायें शौच के लिए, आप उन लोग उसके लिए प्रेरित करें, यह राजद के विधायकों का भी काम है कि वे देखें कि सभी लोग शौचालय में शौच के लिए जायें, कोई खुले में शौच के लिए नहीं जायें । अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय विधायकों ने चिंता प्रकट की थी तो मै बताना चाहूंगा कि अभी तक 56 लाख लोगों के खाते में पैसा भेजा जा चुका है और जो बाकी बचे हुए लोग है उन सभी लोगों के खाते में भी बहुत शीघ्र जो है पैसा भेज दिया जायेगा । अध्यक्ष महोदय, बिहार 2 अक्टूबर को जब पूरा देश खुल में शौच से मुक्त होगा तो बिहार इसमें पीछे नहीं रहेगा । अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, जब बिहार में पशुपालन घोटाला हुआ और यह किसके राज में पशुपालन घोटाला हुआ, ये बताने की आवश्यकता नहीं है तो जिनके राज में पशुपालन घोटाला हुआ और जिसके कारण इनके नेता आज जेल के अन्दर बंद है, अब पता नहीं 18 साल जेल में रहेंगे कि 20 साल जेल में रहेंगे । जब बिहार में पशुपालन घोटाला हुआ तो बिहार के अन्दर जो ट्रेजरी ऑन एकाउन्ट का जो डायरेक्टोरेट था उसको भंग कर दिया गया था । अध्यक्ष महोदय यानी पशुपालन घोटाला के अन्दर तत्कालीन सरकार ने कोषागार एवं लेखा निदेशालय, ट्रेजरी ऐंड एकाउन्टेंट डायरेक्टोरेक्ट को भंग करने का काम किया था । चूंकि पशुपालन घोटाला ट्रेजरी घोटाला था और मैं सदन को बताना चाहूंगा कि अब बिहार सरकार यह निर्णय लेने जा रही है कि हम कोषागार एवं लेखा निदेशालय को फिर से पुनर्गठित करने का काम करेंगे और अध्यक्ष महोदय, अब बिहार की सारी ट्रेजरी ऑनलाईन हो गयी है । अब किसी काम के लिए किसी को ट्रेजरी में जाने की आवश्यकता नहीं है । चाहे वह किसी के वेतन का मामला हो या कोई और मामला हो, अब सारा काम ऑनलाईन है । इस बार 2019-20 का जो बजट बना है वह सी0एफ0एम0एस0 सिस्टम के तहत बना है, बजट का आवंटन, बजट का

निर्माण, रि-ऐप्रोप्रियेशन किसी काम के लिए आपको वित्त विभाग में आने की आवश्यकता नहीं है ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्य सदन से वाकआउट कर गये)

सारी चीजें ऑनलाईन सी0एफ0एम0सी0 के माध्यम से पूरे बजट का निर्माण हुआ है और इसलिए अब सरकार एक निर्णय लेने जा रही है कि इस साल के अंत तक एक अप्रैल 2019 से जितनी सब ट्रेजरी है जो उप कोषागार है अब उनकी आवश्यकता नहीं रहेगी तो हम धीरे धीरे उप कोषागारों की संख्या कम करेंगे और 1 अप्रैल 2019 से बिहार की जितनी सब ट्रेजरी हैं उनको हम बंद कर देंगे । चूंकि सारा काम ऑनलाईन है, आपको अब सबडिवीजन में जाने की जरूरत ही नहीं है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, सारा काम जो मुख्य ट्रेजरी है, वहीं से बैठकर सारा काम हो जायेगा और अध्यक्ष महोदय ट्रेजरी में काम करने वाले जो हमारे कर्मचारी है उनका पदस्थापन हम हर विभाग में जो आंतरिक वित्तीय सलाहकार है, अभी विभाग का कोई एक पदाधिकारी डिप्टी कलक्टर या कोई एक व्यक्ति आंतरिक वित्तीय सलाहकार बन जाता है या जिला के अंदर भी किसी भी एक व्यक्ति को एकाउन्टस का काम देखने के लिए दे दिया जाता है । अब हम इस बात का निर्णय लेने जा रहे हैं कि हर जिला में जिला वित्त प्रकोष्ठ, डिस्ट्रीक्ट एकाउन्ट सेल का गठन किया जायेगा और हर विभाग के अंदर जो विभाग का आंतरिक वित्तीय सलाहकार है, उसको सुदृढ़ किया जायेगा । विभागीय वित्त प्रकोष्ठ जो है उसको भी सुदृढ़ किया जायेगा और वित्त विभाग के अधिकारियों को हर जिले में और हर विभाग में प्रतिनियुक्त किया जायेगा और वे उस विभाग के अंदर बजट का व्यय, उसकी पूरी देख रेख करेंगे। कर्मचारियों का वेतन से लेकर यानी फायनेंस से जुड़े मामले को देखने के लिए जो एकाउन्टस सर्विस के लोग हैं, उनका पदस्थापन किया जायेगा जिनको इसका एक्सपरटाईज हैं जो इसके जानकार हैं तो जिला के अंदर भी और विभागों के अन्दर भी, वित्त विभाग के लोग और आवश्यकता होगी तो नयी नियुक्ति भी करेंगे अन्यथा ट्रेजरी से जो लोग अतिरिक्त हो जायेंगे, सरप्लस होंगे उनको इन विभागों में हम पदस्थापित करेंगे ताकि हमारे जो विभाग है उनका जो खर्च है, उसका जो एकाउन्टिंग सिस्टम है उसको और बेहतर तरीके से हम कर सकें । उसी प्रकार महोदय, जो हमारे राज्य के कर्मचारी हैं, उनको अभी तक वेतन भुगतान के लिए बिल पास कराने के लिए डी0डी0ओ0 को ट्रेजरी में जाना पड़ता था, उनको फिजिकली भी जाना पड़ता था या किसी संदेशवाहक को भेजना पड़ता था बिल पास कराने के लिए ट्रेजरी में और जब बिल पास हो गया तो फिर उसको बैंक में भेजना पड़ता था भुगतान करने के लिए

लेकिन अब ये सारी व्यवस्था समाप्त हो गयी है अध्यक्ष महोदय, अब सी0एफ0एम0एस0,काम्प्रीहेंसिव फायनेंस मैनेजमेंट सिस्टम एक नयी प्रणाली वित्त विभाग ने लागू की है, अब किसी कर्मचारी को, किसी डी0डी0ओ0 को, हमने डी0डी0ओ0 की संख्या भी काफी कम कर दिया है । अब किसी को भी ट्रेजरी में जाने की आवश्यकता नहीं है अब जो बिल बनेगा वह सीधे ऑनलाईन ट्रेजरी में जायेगा, ट्रेजरी में ऑनलाईन सत्यापन होगा, बैंक में जो उसका सत्यापन किया जाना है वह भी ऑनलाईन होगा, बैंक में भी ऑनलाईन जायेगा और आर0बी0आई0 के माध्यम से उसके खाते में उसका पैसा ट्रांसफर हो जायेगा । आज के इधर के दिनों में आपलोग अखबार में पढ़े होंगे कि कुछ कर्मचारियों के वेतन में दिक्कत हो रही है । अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह करूंगा सदन का 2-4 मिनट समय बढ़ा दिया जाय चूंकि लोगों ने काफी समय मेरा ले लिया है, पांच मिनट मुझे और लगेगा।

अध्यक्षः मंत्री जी का वक्तव्य समाप्त होने तक सदन की कार्यवाही का काल बढ़ाया जाता है।

(सभा की सहमति हुई)

श्री सुशील कुमार मोदी,उपमुख्यमंत्रीः तो अध्यक्ष महोदय, राज्य के कर्मचारी का, अभी तक करीब 2 लाख 26 हजार कर्मचारियों का डेटा वेस तैयार हो चुका है । सी0एफ0एम0एस0 सिस्टम में हर कर्मचारी के डेटा वेस को उसमें इंटर किया जाना है और जबतक कर्मचारी का डेटा वेस उसमें इंटर नहीं होगा तबतक उसको वेतन या पैसा नहीं मिलेगा तो यह अधिकांश कर्मचारियों का हो चुका है । इस व्यवस्था से पारदर्शिता आयेगी, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और वित्त विभाग में सारा काम ऑनलाईन होगा। हम कम से कम पेपर का इस्तेमाल करेंगे और सारा काम ऑनलाईन ट्रेजरी के माध्यम से होगा। उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, जो हमारे वर्क्स डिपार्टमेंट है, अभी ठीकेदार को पेमेंट के लिए जाना पड़ता है वर्क्स डिपार्टमेंट में, उनको चेक से पेमेंट होता है उसकी मापी से लेकर जो सारी चीजें है अब इसका भी जो कार्य विभाग हैं वह भी सारा ऑनलाईन हो गया है अब किसी कॉन्ट्रेक्टर को किसी कार्य विभाग के इंजीनियर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चेक से भुगतान नहीं होगा, सारी व्यवस्था ऑनलाईन होगी । वह अपना सारा बिल ऑनलाईन सब्मिट करेगा, वह बिल ऑनलाईन भेरीफाई होगा और भेरीफाई होने के बाद उसका जो पेमेंट होगा वह भी ऑनलाईन जो है सीधे संवेदक के खाते में चला जायेगा इसलिए अध्यक्ष महोदय, एक बड़ा बदलाव वित्त विभाग के अन्तर्गत इस पूरी व्यवस्था के द्वारा किया गया है। अध्यक्ष महोदय, एक और बड़ा निर्णय बड़ा काम वित्त विभाग में हुआ है। आपलोगों ने अमेजन का नाम सुना है, फिलीपकार्ट

का नाम सुना है, किसी को कोई खरीद करनी है तो अमेजन पर जाकर खरीद करते हैं, फिलीपकार्ट पर जाकर खरीद करते हैं। (क्रमशः)

टर्न-15/मधुप/02.07.2019

...क्रमशः ...

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, भारत सरकार ने GeM नाम का एक पोर्टल बनाया है- Government e-Marketplace, तो बिहार सरकार जो खरीद करेगी या प्रोक्योरमेंट करेगी, गाड़ी खरीदना है, किसी नगर निकाय को डस्टबीन खरीदना है, कोई और चीज खरीदना है, स्टेशनरी खरीदना है तो अब विभाग जो भी खरीद करेंगे, तो वे Government e-Marketplace पर जाकर ऑनलाईन परचेज कर सकते हैं । बेचने वाला कौन है यह पता नहीं चलेगा । जो लोग अपना निबंधन करायेंगे उस पोर्टल पर, ऑनलाईन बीडिंग होगी यानी जिसको ऑक्शन होना कहते हैं, ऑनलाईन बीडिंग होगी और जो सबसे कम दर अपना निर्धारित करेगा उससे हम खरीद कर सकेंगे । अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी तक बिहार में जेम पोर्टल के माध्यम से करीब 423 करोड़ रू0 की खरीद हुई है । जो हमारा पुलिस विभाग है, उसमें बड़ी संख्या में गाड़ियों की खरीद होती है, अभी पुलिस विभाग में सारी गाड़ियों की खरीद जेम पोर्टल के माध्यम से हुई है, एक-एक गाड़ी की खरीद में 70 हजार से लेकर 1 लाख रू0 तक की बचत हुई है इस जेम पोर्टल के माध्यम से । इतना ही नहीं, जितने नगर निकाय हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, नगर निकाय ने सारी खरीद अब धीरे-धीरे जेम पोर्टल के माध्यम से प्रारंभ कर दी है । इसकी एक और खासियत है कि अगर आप खरीद करेंगे तो 10 दिन के भीतर वह सामान सप्लाई होने के बाद आपको सर्टिफाई करना है कि सामान सही है, या तो रिजेक्ट कर दीजिये या स्वीकार कर लीजिये । स्वीकार करने के बाद 21 दिन या 15 दिन का एक नियम है, अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपके खाते से सप्लायर के खाते में अपने-आप पैसा चला जायेगा । आज जो सप्लायर को पेमेंट के लिए दौड़ना पड़ता है, चक्कर लगाना पड़ता है, और बहुत तरह की चीजें उसमें सन्निहित रहती हैं, यह जेम पोर्टल जो है, सभी विभागों को यह निर्देश दिया गया है कि 50 हजार से ज्यादा की जो भी खरीद है, जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदें । हमलोगों ने टारगेट किया है कि इस साल 2019-20 में 2000 करोड़ से ज्यादा की खरीद हम जेम पोर्टल के माध्यम से करेंगे । अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर हमलोगों ने, वित्त विभाग ने भी इसके माध्यम से पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है ।

अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के लोग सदन से बाहर चले गये हैं, अगर नेता प्रतिपक्ष सदन में मौजूद रहते तो हमलोगों को खुशी होती । मुझे लगता है कि मेरे 30 साल के संसदीय जीवन का यह पहला मौका है, आज तक मैंने देखा है कि जो भी नेता प्रतिपक्ष रहा है, बजट के भाषण को इनिसियेट करता है लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि नेता प्रतिपक्ष सदन में उपस्थित नहीं हुये, बजट पर हम उनका विचार सुनते, हम जानना चाहते थे कि बिहार सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें क्या कमियाँ हैं, उसके बारे में नेता प्रतिपक्ष को उपस्थित होकर अपनी बातों को कहना चाहिए था लेकिन नेता प्रतिपक्ष 25-30 दिन तक कहाँ थे, पता नहीं है और जब आये, दो दिन हो गया आये हुये तो भी सदन में मौजूद नहीं रहे । अध्यक्ष महोदय, जो लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री नहीं गये, मुख्यमंत्री देर से गये, उनके लिए तो सवाल यह है कि आप कहाँ थे, आप क्यों नहीं गये ? सिद्दिकी साहब क्यों नहीं गये, नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं गये ? अगर अस्पताल में जाने में बाधा पैदा हो रही थी तो उन गरीबों के घर में जाकर आँसू पोछने के लिए जा सकते थे लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये विपक्ष के लोग घड़ियाली आँसू बहाने का काम कर रहे हैं ।

इस बजट पर तो बिहार की जनता ने अपनी मुहर लगा दी, अध्यक्ष महोदय । अभी जो लोक सभा का चुनाव हुआ है, 53 प्रतिशत मत एन0डी0ए0 गठबंधन को प्राप्त हुआ है । आज तक बिहार के इतिहास में कभी किसी गठबंधन को 53 प्रतिशत मत प्राप्त नहीं हुआ था । अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूँगा कि अगर सबसे ज्यादा ताली राज्य के किसी एक योजना के लिए बजती थी तो बिजली को लेकर बजती थी । जब हम लोगों से कहते थे कि 31 दिसम्बर पार नहीं होगा, हम खेतों तक बिजली पहुँचायेंगे तो लोग इसपर सबसे ज्यादा तालियाँ बजाते थे । जो लोग आज चमकी बुखार पर सरकार की आलोचना कर रहे हैं, जो लोग बजट का मजाक उड़ा रहे हैं, एक महीना भी नहीं बीता है कि बिहार की जनता ने 53 प्रतिशत मत देकर विपक्ष के लिए केवल एक सीट देकर हमारी सरकार के कार्यों पर मुहर लगाने का काम किया है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करूँगा और अगले बचे हुये 18 दिनों के अंदर अलग-अलग विभागों पर चर्चा होगी, माननीय मंत्रीगण अपने-अपने विभागों का जवाब देंगे और विस्तृत चर्चा अलग-अलग विभागवार होगी । फिर जब विनियोग विधेयक आयेगा तो मैं फिर एक बार बजट के बारे में अपने विचार रखूँगा । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सरकार का उत्तर समाप्त हुआ और वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श भी समाप्त हुआ ।

आज दिनांक 02 जुलाई, 2019 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 22 (बाईस) है । अगर सदन की सहमति हो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक बुधवार, दिनांक-03 जुलाई, 2019 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

.....